लखनऊ
गुरुवार, 6 अगस्त , 2026
वर्ष : 11 | अंक: 337
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8
UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

मुस्कान एक ऐसी भाषा है, जिसे गूंगा भी समझ सकता है और बहरा भी सुन सकता है।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi
NIGHT 28° Low

संक्षेप

जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, अमरनाथ यात्रा रोकी, आर्टिकल 370 हटने की बरसी पर कश्मीर में सुरक्षा चाक-चौबंद

श्रीनगर। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं बरसी के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एहतियात के तौर पर बुधवार को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई। हालांकि प्रशासन ने यात्रा स्थगित करने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार सुबह जम्मू आधार शिविर से किसी भी नए श्रद्धालु जत्थे को पहलगाम (अनंतनाग) और बालटाल (गांदरबल) आधार शिविरों के लिए रवाना होने की अनुमति नहीं दी गई। इसके साथ ही जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों के काफिलों की आवाजाही भी अस्थायी रूप से रोक दी गई। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कदम आमतौर पर तब उठाया जाता है, जब सुरक्षा एजेंसियां इस महत्वपूर्ण मार्ग पर आवाजाही सीमित रखना चाहती हैं। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला प्रमुख सर्वकालिक मार्ग है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ से पहले जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। पीडीपी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 5 अगस्त को अलग-अलग विरोध कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। प्रशासन ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ ने रामबन में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष जांच अभियान चलाया, जबकि कुलगाम पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की तलाशी और पहचान-पत्रों की जांच तेज कर दी है।

सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, यूएई से भारत लाई गई वॉन्टेड भगोड़ी विशाखा राठौड़

नई दिल्ली, एजेंसी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समन्वय से 88 करोड़ रुपये के निवेश फ्रॉड केस में वॉन्टेड भगोड़ी विशाखा राठौड़ को संयुक्त अरब अमीरात से भारत वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। विशाखा राठौड़ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में वांछित थी। अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश रचकर, उसने निवेशकों को निश्चित मासिक रिटर्न का झूठा वादा करके कई योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया था। विशाखा राठौड़ 3 अगस्त 2026 को पुणे पहुंची और महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। सीबीआई के अनुसार, विशाखा राठौड़ ने बेईमानी से धन का गबन किया। निवेशकों से जो पैसा एकत्रित किया गया था, उसे कई बैंक अकाउंट और डीमैट खातों के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया। आरोपी ने निवेशकों को कई स्कीमों में पैसा लगाने के लिए उकसाया था। उसने लोगों से भारी रिटर्न देने का झूठा वादा किया। बाद में निवेशकों को जब कोई रिटर्न नहीं मिला तो उन्हें पता चला कि वे धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई,

मुख्यमंत्री योगी का सपा पर बड़ा हमला, बोले-

विपक्ष के हंगामे की कीमत युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों ने चुकाई

नई दिल्ली, एजेंसी। विधानसभा के मानसून सत्र में लगातार हो रहे हंगामे को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक रवैये के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई, जिससे प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि सपा ने राजनीतिक विरोध के चलते जनहित के मुद्दों को भी सदन में उठने नहीं दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा सत्र को हंगामे

के हवाले करना लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सदन जनहित के मुद्दों पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच है, लेकिन विपक्ष के रवैये के कारण इसकी गरिमा प्रभावित हुई।

59 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट था केंद्र में

सीएम योगी ने बताया कि सरकार 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट लेकर आई थी। इस बजट में युवाओं के रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, किसानों के कल्याण, महिलाओं के सम्मान एवं स्वावलंबन और गरीबों के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया था। उनका कहना था कि सरकार चाहती थी कि इन योजनाओं पर सदन में विस्तृत चर्चा हो, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया।

'सपा ने जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दी'

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने युवाओं के रोजगार, किसानों की योजनाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबों के कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा को बाधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह

अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल : पीएम मोदी बोले– जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ने विकास का नया दौर देखा

जम्मू। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(ए) हटाए जाने के सात साल आज यानी पांच अगस्त को पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि तब से दोनों क्षेत्रों में लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'आज ही के दिन सात वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35(ए) इतिहास बन गए थे। इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की विकास यात्रा में एक निर्णायक नए अध्याय की शुरुआत हुई।' उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता तथा खेल जैसे क्षेत्रों में नए अवसर बढ़े हैं।

पीएम मोदी ने कहा, 'चाहे महिलाएं हों या वंचित समुदाय, जिन लोगों को दशकों तक अपने मूल संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया, उन्हें भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने के कारण सशक्त बनाया गया है।' उन्होंने कहा कि इस वर्ष 5 अगस्त का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि देश डॉ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका आजीवन समर्पण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उन्होंने दशकों पहले जो सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुआ।' पीएम मोदी ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की प्रगति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है कि हर नागरिक बड़े सपने देख सके, उन्हें पूरा कर सके और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सके।

'56% गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं, इनका चालान काटो', सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली, एजेंसी। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं तो हो सकता है कि निकट भविष्य में आपको पेट्रोल पंप से तेल ने मिले। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सड़कों पर बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के चलने की समस्या से निपटने के लिए यह सुझाव दिया कि जिन गाड़ियों का बीमा नहीं है उनका चालान काटो और ऐसी गाड़ियों को तेल भी मत दो।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि हाईवे और सड़कों पर लगे कैमरों का इस्तेमाल ऐसी गाड़ियों की पहचान करने और उनके मालिकों को चालान भेजने के लिए किया जाए। भारतीय सड़कों पर चलने वाले लगभग 56% वाहनों (जिनमें से ज्यादातर दो-पहिया वाहन हैं) का बीमा न होने पर हैरानी जताते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि इससे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 के तहत अनिवार्य बीमा का मकसद ही खत्म हो जाता है। नतीजतन सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए लंबे कानूनी संघर्ष से गुजरना पड़ता है। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो कुल 30.4 करोड़ रजिस्टर्ड वाहनों में से 16.5 करोड़ वाहन बिना बीमा वाले हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सड़क दुर्घटनाओं में 22% मामले बिना बीमा वाले वाहनों से जुड़े होते हैं। एमवी एक्ट के अनुसार, जो लोग बिना वैलिड मोटर थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाते हैं या चलाने देते हैं। उन्हें कानून तोड़ने के

पीडीए में अब 'पीड़ित पंडित' भी! अखिलेश यादव का ब्राह्मण दांव, बोले– कृष्ण–सुदामा की दोस्ती पुरानी

आर्यावर्त क्रांति

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। इन मुद्दों में राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला, कानून-व्यवस्था, किसानों के लिए खाद की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएँ और सड़क निर्माण परियोजनाएँ शामिल थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलताओं और जनता का भरोसा टूटने वाला रहा है। अखबार

समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद आयोजित 'प्रबुद्धजन सम्मेलन' को संबोधित करते हुए, अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में दिए गए दान में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम की जहाँ उन्हें परमिशन देनी थी, उन्होंने परमिशन नहीं दी इसलिए हमें इस कार्यालय में आयोजन करना पड़ रहा है। जनेश्वर जी को याद करते हुए ये संकल्प लेते है कि उनका मिशन कभी भी रुकेगा नहीं, इसी तरह लगातार चलता रहेगा।

अखिलेश यादव ने कहा कि जबसे PDA से वो लोग हारे हैं तबसे PDA की नई परिभाषा बना रहे हैं, PDA में पीड़ित पंडित भी है। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर एक भी उदाहरण हो जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान न करने से रोका गया हो। उन्हें धरना देना पड़ा लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। समाजवादियों ने बड़े पैमाने पर उनका सम्मान करने का काम किया। ये पेपर लीक नहीं होते, ये सरकार पेपर लीक करवाती है जिससे नौकरी न देना पड़े। हम लोगों ने 30 हजार से ज्यादा भर्ती केवल 9 महीने में कराकर दिखाई थी।

सोनम वांगचुक की अपील पर देवेंद्र महतो ने खत्म की भूख हड़ताल, लाइव बातचीत में मिला रांची आने का भरोसा

रांची, एजेंसी। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर चल रहा युवाओं का संग्राम अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो की जिद के बीच आखिरकार देश के जाने-माने शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दखल देना पड़ा। वांगचुक के एक खास फोन कॉल ने रांची के इस पूरे आंदोलन की दिशा तय कर दी है, जिसके बाद अनशनकारी देवेंद्र ने एक अहम फैसला लिया है। जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो पिछले कई दिनों से अन्न-जल त्यागकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी अटल जिद थी कि जब तक सोनम वांगचुक खुद रांची आकर उनसे मुलाकात नहीं करते, तब तक वह अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे।

परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर एक्शन में सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संभावित संशोधन विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटी है। सूत्रों के अनुसार, संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होने के बाद तत्काल सत्रावसान नहीं किया जा सकता, ताकि जरूरत पड़ने पर जल्द विशेष सत्र बुलाया जा सके। सरकार इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने की दिशा में काम कर रही है। यदि संख्या बल सुनिश्चित हो जाता है तो तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से परिसीमन बिल पर कांग्रेस समेत विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार ने कांग्रेस को कहा है

कि सरकार 16, 17, 18 से संसद का सत्र बुलाना चाहती है। सरकार के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों से चर्चा करके बताएंगे। संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध खत्म करने की कोशिशों के तहत संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। करीब 50 मिनट तक चली इस बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। सूत्रों के मुताबिक रिजिजू ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का सहयोग मांगा, लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि चंदा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बिना सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से नहीं चल सकेगी।

'तीन दिन में माफी मांगें जुकरबर्ग वरना हटा देंगे सेफ हार्बर सुविधा', निशिकांत दुबे का मेटा को अल्टीमेटम

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो हटाए जाने के मामले पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने मेटा को दो टूक शब्दों में तीन दिनों के भीतर माफी मांगने को कहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ₹हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ गृह मंत्रालय को लिखा है कि प्रधानमंत्री का वीडियो हटाना किसी मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) की नहीं, बल्कि पब्लिशर की जिम्मेदारी थी।" भाजपा सांसद ने आगे कहा, "इसके चलते मार्क जुकरबर्ग को तीन दिन के अंदर माफी मांगनी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अभी मिल रही सेफ हार्बर सुविधा को वापस ले लेंगे।"

नितिन गडकरी के खिलाफ ऑनलाइन पोस्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश

मुंबई, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ ऑनलाइन पोस्ट को लेकर बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ की गई ऑनलाइन पोस्ट घिनौने, अश्लील, अपमानजनक और मानहानि करने वाले हैं। कोर्ट ने ऐसे सभी पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। दरअसल, ई20 फ्यूल को लेकर चल रहे विवाद के बीच कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।

जस्टिस आरिफ डॉक्टर की सिंगल बेंच ने गडकरी को अंतरिम राहत दी। इसके साथ ही मेटा, X कॉर्प और गूगल LLC को निर्देश दिया कि वे तुरंत इन पोस्ट को हटाने का इंतजाम करें। कोर्ट ने कहा, 'ये पोस्ट देखने में ही अपमानजनक, घिनौने और अश्लील हैं।' बेंच ने मेटा, X कॉर्प और गूगल LLC जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यह भी पूछा, 'आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, जो ऐसे मामलों को तुरंत पकड़ सके? अगर कोई अश्लील या अपमानजनक चीज पोस्ट करता है, तो उसे तुरंत पकड़कर हटा दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही घिनौनी बात है। कोई जहर उगल रहा है।' कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में ऐसी कोई पोस्ट अपलोड की जाती है, जिसमें डीपफेक या एआई से बना कंटेंट भी शामिल हो,तो मंत्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संपर्क कर सकते हैं। वे इस पर कार्रवाई करेंगे। यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से गडकरी को मेटा, X कॉर्प (पहले ट्विटर), गूगल LLC और दूसरे प्लेटफॉर्म के खिलाफ सिविल केस करने की इजाजत देने के कुछ दिनों बाद आया है। यह केस सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाने वाली कथित मानहानि वाली पोस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने डीपफेक कंटेंट को लेकर है।

'कल जेन अल्फा, बीटा आ जाएगी': छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने को लेकर वकील की दलील, सीजेआई सूर्य कांत ने क्या कहा?

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को किसी राजनीतिक फैसले के आधार पर वापस लिया गया, तो

यह भविष्य के आंदोलनों के लिए खतरनाक मिसाल बन जाएगी। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, कल जेनरेशन अल्फा, बीटा, डेल्टा भी आएगी।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि हाल के छात्र प्रदर्शनों में हिंसा से जुड़े मामलों को केवल किसी राजनीतिक समझौते के आधार पर वापस न लिया जाए। चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने इस मामले को छात्र प्रदर्शनों से जुड़े अन्य मामलों के साथ जोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जा सकती हैं। मनीष कुमार सोलंकी की ओर से दायर याचिका में प्रदर्शन के आयोजकों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है।

सीजेआई सूर्य कांत ने क्या कहा?

सीजेआई ने कहा, इस स्थिति को बहुत सावधानी से संभालने की जरूरत है। युवाओं को भरोसा दिलाना होगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को भी बहुत संयम बरतना चाहिए, ताकि अगर कोई घटना हो भी जाए तो हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं। उन्होंने आगे कहा, हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा, ताकि युवा हिंसा का रास्ता न अपनाएं। जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, बेहतर तरीका यही है कि उन्हें समझाया जाए और शांत किया जाए कि सबसे ताकतवर व्यवस्था उनकी बात सुन रही है। इसके बाद बेंच ने इस मामले को पहले से लंबित दूसरे मामलों के साथ जोड़ दिया।

याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा?

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रिजवान अहमद ने कहा, यह प्रदर्शन मंत्री और पुलिस की जवाबदेही को लेकर था। हम इसे स्वीकार करते हैं। 15 दिन बीत चुके हैं। लेकिन आयोजकों की जवाबदेही का क्या? वे एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं और आग को शांत करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, इन तथाकथित आयोजकों की जवाबदेही कहां है? मैं उन्हें तथाकथित आयोजक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह कोई पंजीकृत संगठन नहीं है। उनका इशारा 'कॉकरोच जनता पार्टी' की ओर था, जिसने नीट 2026 पेपर लीक के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया था। रिजवान अहमद ने कहा कि कानून के मुताबिक किसी भी सभा या प्रदर्शन के दौरान अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए आयोजक भी जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों की मांग मानते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर सहमत हो गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे भविष्य में गलत उदाहरण बनेगा। उन्होंने कहा, कल राजस्थान में कानून-व्यवस्था की एक घटना हुई।

वकील ने क्या दलील दी?

वकील रिजवान अहमद ने स्पष्ट किया कि वह छात्रों को कड़ी आपराधिक सजा देने की मांग नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जो नाबालिग प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे, उनसे सामुदायिक सेवा कराई जा सकती है।

हालांकि उन्होंने कहा, जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि सरकार की गलती सामने आ गई।

उन्होंने दलील दी कि अगर ऐसे मामलों को माफ किया गया, तो दूसरे समूह भी संसद तक इसी तरह के प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे।

उन्होंने कहा, किसान शंभू बॉर्डर पर थे। कल जेनरेशन अल्फा, बीटा, डेल्टा आएगी। क्या शंभू बॉर्डर वाले कल ट्रैक्टर लेकर संसद आ जाएंगे? कल शाहीन बाग के लोग संसद पहुंच जाएंगे।

रिजवान ने कहा, अगर 500 लोग संसद में घुस जाते, तो कौन जानता कि उनके पास देसी बंदूक या देसी बम नहीं होता?

शामली में बड़ा पुलिस एनकाउंटर, कैराना पलायन का आरोपी बदमाश फुरकान ढेर, एक लाख का था इनामी

आर्यावर्त संवाददाता

शामली। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव रंगाना के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपए का इनामी बदमाश फुरकान मारा गया। मुठभेड़ के दौरान फुरकान ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी के पेट में गोली लग गई, जबकि दो अन्य पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोलियां लगीं। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

पुलिस के अनुसार, फुरकान लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा था और उस पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित था। फुरकान के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, जानलेवा हमला और अन्य गंभीर अपराधों समेत 30 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वह कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य माना जाता था।

फुरकान का नाम कैराना के चर्चित पलायन मामले में भी सामने आया था। आरोप है कि वर्ष 2014 में उसने मुकीम काला गैंग के साथ मिलकर व्यापारियों से रंगदारी वसूलने और उन्हें धमकाने का काम किया। पुलिस के मुताबिक, रंगदारी नहीं देने पर व्यापारियों की हत्या तक कर दी जाती थी। इन्हीं घटनाओं के बाद कैराना के कई व्यापारी और परिवार डर के कारण अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों और राज्यों में चले गए थे। उस समय यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना था।

व्यापारी की हत्या के बाद फैला था खौफ

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फुरकान पर दिनदहाड़े व्यापारी विनोद सिंघल की हत्या करने का भी आरोप था। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उसने फिर से व्यापारियों को धमकाना और रंगदारी मांगना शुरू कर दिया था। लगातार हो रही वारदातों से इलाके में भय का माहौल बन गया था और कई परिवारों ने पलायन कर लिया था। बताया जाता है कि करीब 346 परिवारों ने उस समय कैराना छोड़ दिया था।

घटनास्थल से हथियार बरामद

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक कार्बाइन, एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि फुरकान का एक साथी मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश के लिए आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस फुरकान के अन्य साथियों और उसके आपराधिक नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

एसपी ने दी पूरी जानकारी

शामली के पुलिस अधीक्षक एन।पी। सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 में मुकीम काला और फुरकान ने कैराना में आतंक का माहौल बना रखा था। उन्होंने बताया कि मात्र 10 दिनों के भीतर रंगदारी न देने पर तीन व्यापारियों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके से लोगों का पलायन शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि फुरकान इस गिरोह का सक्रिय सदस्य था और उसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी।

मुकीम काला गैंग पर लगातार कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, कुख्यात अपराधी मुकीम काला की कुछ वर्ष पहले चित्रकूट जेल में गैंगवार के दौरान मौत हो चुकी है। हाल के वर्षों में उसके कई शूटर भी पुलिस मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि फुरकान इस गैंग का बचा हुआ प्रमुख अपराधी था, जिसके मारे जाने के बाद गैंग की गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा।

कीचड़, गड्ढे और झाड़ियां बनीं विकास की पहचान!

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। तहसील क्षेत्र का लँगड़ी बाजार-विसावां मार्ग इन दिनों बदहाल व्यवस्था और विभागीय उदासीनता की जीती-जागती तस्वीर बन गया है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे, कीचड़, जलभराव और फुटपाथ पर उगी झाड़ियां राहगीरों व स्कूली छात्रों के लिए रोजाना खतरा बन चुकी हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे षगड्ढामुक्त सड़क अभियानष के दावों की इस मार्ग पर पूरी तरह पोल खुलती दिखाई दे रही है।

छात्रों की सुरक्षा भगवान भरोसे

लँगड़ी बाजार में हनुमत जूनियर हाई स्कूल, मंगला प्रसाद इंटर कॉलेज और महाराणा प्रताप विद्यालय स्थित हैं। प्रतिदिन लगभग आधा दर्जन ग्राम सभाओं के सैकड़ों छात्र-छात्राएं इसी मार्ग से विद्यालय आते-जाते हैं। सड़क पर फैले कीचड़ और गहरे गड्ढों के कारण बच्चों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। बरसात के दौरान गड्ढों में भरा पानी दुर्घटनाओं की आशंका और बढ़ा देता है।

पीडब्ल्यूडी और ग्राम पंचायत दोनों सवालों के घेरे में

सड़क की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है, लेकिन लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं होने से विभागीय कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे नालियों का निर्माण न होने से बारिश का पानी सड़क पर भर जाता है, जिससे कीचड़ और जलभराव की समस्या विकराल हो गई है। इससे ग्राम पंचायत और संबंधित जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली भी कटघरे में है।

फुटपाथ पर झाड़ियां, पैदल चलना भी मुश्किल

सड़क किनारे बने फुटपाथों पर झाड़ियां और घास उग आने से पैदल चलने वालों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ता है। तेज रफ्तार वाहनों के बीच यह स्थिति कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो झाड़ियों की सफाई कराई गई और न ही सड़क की मरम्मत।

शासन की मंशा पर भ्रष्ट तंत्र भारी

प्रदेश सरकार लगातार सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और नियमित रखरखाव के निर्देश जारी कर रही है। इसके बावजूद धरातल पर जिम्मेदार अधिकारी इन आदेशों को गंभीरता से लागू नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क मरम्मत के नाम पर बजट तो खर्च दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविक कार्य नजर नहीं आता। यदि समय रहते सड़क की मरम्मत, नाली निर्माण और झाड़ियों की सफाई नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

जनता की मांग

क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग और संबंधित अधिकारियों से लँगड़ी बाजार - विसावां मार्ग की तत्काल मरम्मत, जलनिकासी के लिए नालियों का निर्माण तथा फुटपाथ से झाड़ियों की सफाई कराने की मांग की है, ताकि छात्रों, किसानों और आम राहगीरों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।

छेड़छाड़ के मुकदमे में समझौते के लिए बुलाकर युवक पर हमला

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। जानी थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा ग्रामीण ने मुकदमा दर्ज कर दिया। आरोपी के भाई का आरोप है कि मुकदमे में समझौते के लिए बुलाकर दूसरे पक्ष द्वारा उस पर हमला करते हुए उसे जमकर पीटा गया। मारपीट का वीडियो लेकर एसएसपी से मिलने पहुंचे पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

जानी थाना क्षेत्र के जानी गांव का रहने वाला मोमीन बुधवार को अपने परिवार के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा। मोमीन ने बताया कि उसका बड़ा भाई गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के घर पर मजदूरी करता था। मोमीन का आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मोमीन के भाई पर मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद मोमीन और उसके परिवार को मुकदमे में समझौते की बातचीत के लिए शहजाद के घर पर बुलाया।

आरोप है कि यहां लड़की पक्ष के लोगों ने अपने कई साथियों के साथ मोमीन और उसके परिजनों की जमकर पिटाई की। जिसमें मोमीन का हाथ भी टूट गया। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन, इसके बावजूद पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की।

मारपीट का लाइव वीडियो लेकर एसएसपी से मिलने पहुंचे पीड़ित पक्ष ने आरोपी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिस पर अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं।

नोएडा में लोकसभा सचिवालय के निदेशक ने फ्लैट में लगाई फांसी, जांच में जुटी पुलिस

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा के थाना फेस-2 क्षेत्र स्थित केंद्रीय विहार-2 सोसाइटी में रहने वाले लोकसभा सचिवालय के निदेशक पद पर कार्यरत एक अधिकारी ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

2 अगस्त को मिली थी घटना की सूचना

थाना फेस-2 पुलिस के अनुसार, अस्पताल से एक मेमो के जरिए सूचना मिली कि केंद्रीय विहार-2 निवासी गौरव गौतम (40) ने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। गौरव गौतम, पदम सिंह के पुत्र थे और लोकसभा सचिवालय में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई।

फॉरेंसिक टीम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के साथ फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की प्रक्रिया पूरी की गई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में किसी तरह की संदिग्ध परिस्थिति सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हर पहलू से की जा रही जांच

थाना फेस-2 पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आत्महत्या के पीछे कोई व्यक्तिगत, पारिवारिक या अन्य कारण तो नहीं था। पुलिस परिजनों से भी जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा।

कन्नौज में सपा नेता ने गाय पर छोड़ा अपना पालतू कुत्ता, पशु क्रूरता का केस दर्ज; सीसीटीवी हुआ वायरल

आर्यावर्त संवाददाता

कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सदर कोतवाली क्षेत्र के बालापीर स्थित एक गेस्ट हाउस के पास आवारा गाय के साथ पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति अपने तीन पालतू कुत्तों को एक गाय की ओर छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो में समाजवादी पार्टी से जुड़े बताए जा रहे नेता कैश खां अपने पालतू कुत्तों को बार-बार गाय की ओर छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुत्तों के हमले से बचने के लिए गाय इधर-उधर भागती नजर आती है। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि पड़ोसी अदील खान ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार से की थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस ने कैश खां के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार कैश खां के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जनवरी माह में उनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई भी की गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी तक उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है।

आरोपी ने क्या बताया?

मामले में जब कैश खां से पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बताया कि वह और उनके पिता इस समय शहर से बाहर हैं। वहीं शिकायतकर्ता अदील खान से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि वह अपनी मां का इलाज कराने के लिए कानपुर गए हुए हैं और शिकायत उनके द्वारा ही दर्ज कराई गई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार से भी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है।

अमीर बनने की चाह में बनी ठग! रेलवे अफसर की बेटी ने 1.67 करोड़ की कर डाली ठगी; अरेस्ट

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एम्स थाना क्षेत्र के महादेव झारखंडी के रहने वाले स्टेशन मास्टर ध्रुव नारायण सिंह और उनकी बेटी गरिमा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने 1.67 रुपए की ठगी की है। पुलिस ने दोनों को 3 जुलाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गरिमा सिंह के पास से मिली डायरी में गरिमा सिंह ने लिखा है कि "अप्रैल 2026 तक अरबपति बनूंगी, यह मेरा लक्ष्य है। डायरी में गरिमा ने लिखा है कि मेरे सभी लोन अप्रैल तक खत्म हो जायेंगे। डायरी में ये भी लिखा है कि अप्रैल से मई तक मेरा लक्ष्य 100 करोड़ रुपए कमाना है। गरिमा सिंह करोड़पति है, धन्यवाद भगवान।।"

गोरखपुर में रेलवे स्टेशन अधीक्षक की बेटी गरिमा सिंह ने अमीर बनने के लिए गलत रास्ता चुन लिया। उन्होंने लोगों को लोन दिलाने उन्हें लोन माफ कराने के नाम पर लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए की ठगी की है। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के महादेव झारखंडी कॉलोनी में रहने वाले ध्रुव नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के सहजनवा रेलवे स्टेशन अधीक्षक है। उनकी बेटी गरिमा सिंह कम समय में ज्यादा रुपए कमाने के लिए गलत रास्ता चुन लिया। गरिमा सिंह और उसके पिता धूप नारायण सिंह ने जाल साजी कर 1.6 करोड़ रुपए की ठगी की है। तलाशी में गरिमा के पास से एक डायरी मिली है जिसमें गरिमा ने खुद के बेहद अमीर होने और बेशुमार दौलत मिलने की बाते लिख रखी थी। 1 अगस्त को साथी रेलकर्मी सत्य प्रकाश सिंह द्वारा एम्स थाने में दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता और पुत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने कार लोन चुकता करने और पर्सनल लोन दिलाने का झांसा देकर छह अलग-अलग बैंकों से 1.67 करोड रुपए का लोन पास कराया और रकम अपनी पास रख ली थी। सत्य प्रकाश सिंह ने पाने तहरीर में बताया है कि ध्रुव नारायण ने कार लोन चुकता करने का वादा कर अपनी बेटी से मुलाकात करवाई थी। गरिमा ने उनके दस्तावेज का इस्तेमाल कर ICICI, SBI, YES, HDFC, SNFG AUR BNDHAN BANK में पर्सनल लोन कराया, जिसमें से 10 लाख रुपए सत्य प्रकाश सिंह के खाते में डाल कर 3 महीने की EMI भरी। उसके बाद उन्होंने किस्त देना बंद कर दिया था।

जल्दी अमीर बनना चाहती थी बेटी

गरिमा सिंह की शादी 2020 में कुशीनगर जिले की सुकरौली के रहने वाले भानु प्रताप सिंह से हुई थी। गरिमा का पति ठेकेदारी करता था। गरिमा के पति भानु का ठेकेदारी का काम जब कमजोर होने लगा तो वह अपनी पत्नी के साथ उसके घर आ कर रहने लगा। आरोपी पिता ध्रुव सिंह ने बताया कि उसकी बेटी गरिमा सिंह को अमीर बनने का बहुत ही शौक था, जिसके लिए उसने इंटरनेट के माध्यम से ठगी करने वाले लोगों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उसने प्लानिंग करके लोगों को बैंक से लोन दिलाने और लोन की रकम माफ कराने के लिए लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि इस कार्य में वह भी बेटी की मदद करने लगे। उन्होंने बताया कि रेलवे में जो लोग उनके जानने वाले थे उनको अपनी बेटी से मिलवाया।

किन लोगों को बनाती थी शिकार?

पुलिस के मुताबिक, गरिमा सिंह दो तरह के लोगों को अपना शिकार बनाती थी। वह लोग जिन लोगों को लोन की जरूरत है और दूसरे वह लोग जो लोग पहले से ही लोन ले रखे हैं। गरिमा उन लोगों से मिलकर उनका ब्रेनवाश करती थी और फिर उन्हें झांसे में लेकर उन्हें अपने ठगी का शिकार बनाती थी। वह लोगों से कह रही थी कि आप लोन ले लो किस्त मैं भर दूंगी। गरिमा इतनी शातिर थी कि वह जिसको लोन दिलवाती थी उसका 10 से 20 प्रतिशत वह लोन लेने वाले को दे दी थी। बाकी रकम अपने बैंक में ट्रांसफर करवा लेती थी। वहीं, इस मामले में एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि लोन के नाम पर रुपए हड़पने का ममला सामने आया है। पिता और पुत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है।

सपा भी सर्वे की राह पर, साइकिल की सवारी को सामने आए इतने नाम

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए मुरादाबाद में भाजपा की तरह सपा भी सर्वे की राह पर है। अभी तक हुए सर्वे के दो चरणों में साइकिल की सवारी के लिए नगर और कुंदरकी सीट पर आठ दावेदारों के नाम सामने आ चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि सर्वे करने वाली एजेंसी के सामने नगर सीट से जो चार नाम सामने आए हैं, उनमें तीन हिंदू हैं।

सर्वे के इस फीडबैक को अगर सपा टिकट के फैसले में आधार बनाती है और नगर विधानसभा क्षेत्र से सपा किसी हिंदू को आजमाती है तो भाजपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। सियासत में धीरे-धीरे व्यापक सोच को तरजीह दे रही सपा ने मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र में रुचिवीरा को उम्मीदवार बनाकर भी विपक्षियों को चौंका दिया था।

दूसरे दलों का मानना था कि मुरादाबाद से सपा का उम्मीदवार हिंदू हो ही नहीं सकता। तब विपक्षियों को चकमा देते हुए सपा ने मुरादाबाद में रुचिवीरा का टिकट भी अंतिम समय में तय किया था। मुस्लिमों के साथ-साथ हिंदुओं में भी लोकप्रिय पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन को मैदान से हटाकर रुचिवीरा को उम्मीदवार बनाया था।

इस सबके बीच चुनाव परिणाम रुचिवीरा के पक्ष में आने से यह संदेश भी गया था कि सांगठनिक स्तर पर ही नहीं, सपा के कोर वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिमों की सोच भी बदल रही है।

सपा के लिए अभी तक दो सर्वे हुए

पार्टी सूत्रों के मुताबिक सपा के लिए अभी तक दो सर्वे हो चुके हैं। ये दोनों सर्वे जिले में भाजपा के कब्जे वाली सीट मुरादाबाद नगर और कुंदरकी पर कराए गए हैं। अब तक के दो सर्वे में नगर और कुंदरकी सीट के लिए लोगों के बीच आठ दावेदारों के नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा रही।

इनमें मुरादाबाद नगर सीट से पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी, जिलाध्यक्ष जयवीर यादव, लाखन सिंह सैनी और राहुल सिंह के नाम शामिल हैं। जबकि कुंदरकी सीट से पूर्व विधायक हाजी रिजवान, पूर्व विधायक अकीलुर्रहमान, जिला पंचायत सदस्य नावेद बबलू और अनीस चौधरी के नाम चर्चाओं में रहे।

सर्वे में नगर सीट से भले ही उक्त नामों की चर्चा रही हो लेकिन इसके अलावा कुछ और सपा नेताओं के नाम भी हैं, जो टिकट के मजबूत दावेदारों में हैं। फिलहाल जिला स्तर पर अभी टिकट के दावेदारों के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। प्रदेश स्तर से इस बाबत कोई दिशा निर्देश भी जारी नहीं किए गए हैं।

> सर्वे प्रदेश स्तर से कराए जाते हैं, जो गोपनीय होते हैं। सर्वे करने वाली एजेंसी सीधे प्रदेश नेतृत्व के संपर्क में रहती है। विधानसभा टिकट के लिए अभी आवेदन लेने की शुरुआत नहीं हुई है।
>
> - जयवीर यादव, जिलाध्यक्ष, सपा

नगर सीट के दावेदारों में ये भी शामिल

नगर सीट से सपा के टिकट के दावेदारों में अतहर अंसारी, सरताज अंसारी, तालिब अंसारी, इमरान, बीके सैनी, जयपाल सिंह सैनी, राजीव सिंघल, नरेश शर्मा के नाम शामिल हैं। वहीं, कुंदरकी सीट से जिला पंचायत सदस्य राबुल पाशा, आशकार पाशा के नाम भी चर्चा में हैं।

कुंदरकी सीट पर दो सांसदों की भी नजर

कुंदरकी सीट पर दो सांसदों की भी नजर है। ये दोनों सांसद दूसरे जिले से ताल्लुक रखते हैं। इसमें एक सांसद अपने पिता और दूसरे सांसद अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं, एक विधायक की भी कुंदरकी सीट पर निगाह है।

उपचुनाव में सपा ने गंवाई थी कुंदरकी सीट

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जिले की छह में से पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि जियाउर्रहमान बर्क के सांसद बनने पर कुंदरकी में हुए उपचुनाव में सपा यह सीट हार गई थी। मुरादाबाद नगर सीट पर पिछले दो चुनाव से सपा को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है।

नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सुनहरा मौका, YEIDA लाएगा 40 से 300 वर्गमीटर तक के प्लॉट

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) घर खरीदने वालों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। नवरात्र के मौके पर प्राधिकरण दो नई आवासीय भूखंड योजनाएं लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इन योजनाओं के तहत 40 वर्गमीटर से लेकर 300 वर्गमीटर तक के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिन्होंने पहले कभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण की किसी आवासीय योजना में प्लॉट नहीं लिया है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक हब और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के कारण यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। इसी वजह से यहां रहने और निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ती मांग को देखते हुए यमुना प्राधिकरण ने नए आवासीय सेक्टर विकसित करने की योजना बनाई है, ताकि आम लोगों को भी एयरपोर्ट के पास घर बनाने का अवसर मिल सके।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, दोनों आवासीय योजनाएं सेक्टर-5ए में लाई जाएंगी। यह सेक्टर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब पांच मिनट की दूरी पर स्थित है। इसी इलाके में भविष्य में प्रस्तावित जापानी सिटी भी विकसित की जानी है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सबसे आधुनिक और विकसित शहरी क्षेत्रों में शामिल होगा।

59 हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट से किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों को मिलेगा लाभ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले नौ वर्षों से समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक के अनुपूरक बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है।विधान भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा से पारित होने के बाद यह अनुपूरक बजट विधान परिषद में पारित होगा। इसके बाद विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के

माध्यम से इसका लाभ प्रदेश के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में नई योजनाओं के साथ प्रदेश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने तथा एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, रसोइयों, ग्राम चौकीदारों और कोटेदारों के मानदेय में वृद्धि के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा निराश्रित महिलाओं, वृद्धावस्था और दिव्यांगजन पेंशन में वृद्धि के लिए भी सरकार प्रयासरत है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को न्यूनतम मानदेय और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षामित्रों का मानदेय 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये किया गया है तथा उन्हें पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। वहीं अनुदेशकों का मानदेय 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये किया गया है। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय के महान पुरोधाओं बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर, महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, संत ज्योतिबा फुले, लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर और छत्रपति शाहू जी महाराज के सम्मान में उनकी प्रतिमाओं पर छाजन, सुरक्षित पार्क और चारदीवारी के निर्माण के लिए अनुपूरक बजट में 407 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राम मंदिर चढ़ावा मामले और किसानों की खाद पर चर्चा से सरकार भागी : आराधना मिश्रा मोना

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को निर्धारित समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने पर कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जनता के मुद्दों से बचने का आरोप लगाया।आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि कांग्रेस ने नियम 311 और नियम 56 के तहत रामलला मंदिर में चढ़ावा और चंदे में कथित अनियमितताओं तथा प्रदेश में किसानों के लिए खाद की कमी के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने चर्चा कराने के बजाय विधानसभा को समय से पहले स्थगित कर दिया।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन नहीं कर रही है और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। उनका कहना था कि यदि सरकार के पास

पूर्ण बहुमत था तो चर्चा से बचने की आवश्यकता नहीं थी।

कांग्रेस नेता ने रामलला मंदिर के चढ़ावे, चंदे, भूमि खरीद, आयोजनों और खर्च से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने तथा जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करने से बच रही है।आराधना मिश्रा मोना ने यह भी कहा कि सरकार किसानों की खाद की समस्या, छात्रों से जुड़े मुद्दों और अन्य जनहित के विषयों पर भी सदन में चर्चा नहीं कराना चाहती। उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब विधानसभा का सत्र 6 अगस्त तक निर्धारित था, तो उसे समय से पहले समाप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

कानपुर–लखनऊ एक्सप्रेसवे में धंसाव पर बड़ी कार्रवाई, निर्माण एजेंसी व अधिकारियों पर गिरी गाज

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। कानपुर–लखनऊ एक्सप्रेसवे में धंसाव और निर्माण गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने संबंधित निर्माण एजेंसी और अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने प्रेस वार्ता में बताया कि निर्माण कार्य में लापरवाही पाए जाने पर निर्माण कंपनी को खराब प्रदर्शन करने वाली एजेंसी घोषित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। कंपनी पर प्रदर्शन सुरक्षा राशि का दो प्रतिशत तक जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है।प्राधिकरण के अनुसार, प्रभावित हिस्से की मरम्मत निर्माण कंपनी अपने खर्च पर करेगी और इस पर प्राधिकरण का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। परियोजना से जुड़े परियोजना प्रबंधक, दल प्रमुख और आवासीय अभियंता को उनके दायित्वों से हटा दिया गया है। साथ ही तीन अधिकारियों को दो वर्षों तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम की परियोजनाओं में कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वर्तमान और पूर्व परियोजना निदेशकों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।स्वतंत्र अभियंता संस्था को भी प्रतिबंधित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। धंसाव के कारणों की तकनीकी जांच के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि मरम्मत कार्य पूरा होने तक एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क की वसूली बंद रहेगी तथा इससे होने वाले नुकसान की भरपाई निर्माण कंपनी से कराई जाएगी।

घरेलू विवाद में मारपीट से घायल व्यक्ति की मौत, पत्नी और पुत्र गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। निगोहां थाना पुलिस ने घरेलू विवाद के दौरान हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत होने के मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।पुलिस के अनुसार, 4 अगस्त को मीरक नगर निवासी 54 वर्षीय कैलाश चन्द्र की उपचार के दौरान मृत्यु होने की सूचना मिली। जांच में पता चला कि 3 अगस्त की देर शाम शराब के नशे में घर पहुंचे कैलाश चन्द्र का घरेलू बातों को लेकर पत्नी और पुत्र से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों ने उनके साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल कैलाश चन्द्र का एक निजी अस्पताल

में उपचार चल रहा था, जहां उनकी मृत्यु हो गई।मृतक की मां रामपति की तहरीर पर निगोहां थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पुत्र अरुण कुमार उर्फ शिवम कुमार गौतम (22) और पत्नी लज्जावती (45) को गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में आरोपी पुत्र ने बताया कि उसके पिता शराब पीने के आदी थे और इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन भी विवाद बढ़ने पर उसने और उसकी मां ने मिलकर कैलाश चन्द्र के साथ मारपीट की थी। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

चेकिंग के दौरान तमंचा और चार जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

लखनऊ। सुशान्त गोल्फ सिटी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध देशी तमंचा और चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक, 4 अगस्त को स्टंटबाजी करने वाले बाइक सवारों, तीन सवारी, परिवर्तित साइलेंसर, हूटर तथा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस टीम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय चौराहे के पास वाहनों की जांच कर रही थी।इसी दौरान स्वाती अपार्टमेंट की ओर से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस को देखकर वापस भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से .315 बोर का एक अवैध देशी तमंचा और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

सावन में विधान परिषद सदस्यों को भेंट किए गए रुद्राक्ष के पौधे

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। सावन मास के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह ने विधान परिषद के सभी सदस्यों को भगवान शिव के पावन प्रतीक रुद्राक्ष के पौधे भेंट किए।इस अवसर पर रुद्राक्ष के धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि रुद्राक्ष एक सदाबहार और विशाल वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम Elaeocarpus ganitrus है। यह मुख्य रूप से हिमालय की तराई, नेपाल और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में यह 18 से 24 मीटर तक ऊंचा हो सकता है, जबकि इसे घरों और उद्यानों में भी आसानी से लगाया जा सकता है।रुद्राक्ष की पत्तियां चमकदार हरी, फूल छोटे, सफेद और सुगंधित होते हैं। इसके हरे फल पकने पर नीले रंग के हो जाते हैं, जिनके भीतर रुद्राक्ष का पवित्र बीज होता है। उपयुक्त देखभाल मिलने पर यह तीन से चार वर्ष में फल देना शुरू कर देता है।प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रुद्राक्ष का पौधा गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह विकसित होता है। जल निकास वाली दोमट मिट्टी तथा जैविक पदार्थों से युक्त भूमि इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है।विज्ञप्ति में बताया गया कि 'रुद्राक्ष' शब्द संस्कृत के 'रुद्र' और 'अक्ष' से मिलकर बना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रुओं से हुई थी। इसके बीजों पर प्राकृतिक रूप से एक से 21 मुख पाए जाते हैं, जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है।प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि रुद्राक्ष का पौधा सकारात्मक ऊर्जा, शांति, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक वायु शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। इसके बीजों का उपयोग जप, ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना में व्यापक रूप से किया जाता है।

फर्जी दस्तावेज बनाकर नवजात सौंपने का मामला उजागर, दो महिलाएं गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की अपराध शाखा और गुडम्बा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने नवजात शिशु के अवैध हस्तांतरण और फर्जी चिकित्सीय अभिलेख तैयार कर कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को दरकिनार करने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि संबंधित चिकित्सकों और अस्पताल प्रशासन की भूमिका की भी जांच की जा रही है।पुलिस के अनुसार, 3 अगस्त को सूचना मिली थी कि गुडम्बा क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में जन्मे नवजात शिशु को उसकी जैविक मां से अलग कर दूसरी महिला को सौंप दिया गया। साथ ही अस्पताल के अभिलेखों में वास्तविक प्रसूता के स्थान पर दूसरी महिला का नाम दर्ज कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए।जांच के दौरान नवजात शिशु रेनू शर्मा के पास मिला। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि बच्चा उसका जैविक पुत्र नहीं है और उसे आरती देवी ने सौंपा था। इसके बाद आरती देवी से पूछताछ की गई। उसने बताया कि पहले से तीन बच्चे होने के कारण उसने अपना नवजात शिशु रेनू शर्मा को दे दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि अस्पताल में प्रसव संबंधी अभिलेख वास्तविक प्रसूता के बजाय दूसरी महिला के नाम से तैयार किए गए थे।प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर गुडम्बा थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(2), 319(2), 336(3) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धाराओं 80 और 81 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों महिलाओं का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। नवजात शिशु को बाल कल्याण समिति के आदेश पर प्राग नारायण रोड स्थित राजकीय बाल गृह (शिशु) में सुरक्षित रखा गया है।पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना वैज्ञानिक और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। अस्पताल के मूल अभिलेख, जन्म एवं डिस्चार्ज रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय साक्ष्यों की जांच की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर डीएनए परीक्षण भी कराया जाएगा। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस मामले में अस्पताल के चिकित्सकों, कर्मचारियों या किसी संगठित गिरोह की संलिप्तता तो नहीं है।पुलिस ने आमजन से अपील की है कि बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया केवल किशोर न्याय अधिनियम और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही अपनाई जाए। किसी भी निजी समझौते, फर्जी दस्तावेज, अस्पताल, नर्सिंग होम या बिचौलिये के माध्यम से बच्चे का हस्तांतरण कानूनन अपराध है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

लखनऊ। सैरपुर थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया।पुलिस के अनुसार, 4 अगस्त को पीड़िता ने सैरपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर थाना सैरपुर में मुकदमा संख्या 92/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई।मामले की विवेचना के दौरान पुलिस टीम आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सीतापुर रोड स्थित दूध मंडी के पीछे से आरोपी शिवराम यादव उर्फ विवेक यादव (23), निवासी कमला नगर, थाना जानकीपुरम, लखनऊ को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के अनुसार, आरोपी वाहन चालक है।

विपक्ष ने तीन दिन तक सदन की कार्यवाही बाधित की, फिर भी सरकार ने सभी विधायी कार्य पूरे किए : शर्मा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विधानसभा और विधान परिषद के मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार की विकासपरक नीतियों और ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की नारेबाजी के बावजूद सरकार ने अपने सभी महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को पूरा किया और अनुपूरक बजट भी सफलतापूर्वक पारित कराया।सदन में अपने संबोधन के दौरान ए.के. शर्मा ने कहा कि आजादी के कई दशकों तक उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। लाखों घरों में बिजली नहीं थी और अनेक मजरों तक बिजली के खंभे और तार भी नहीं

पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने लगभग डेढ़ लाख मजरों तक बिजली पहुंचाकर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वाधिक बिजली मांग की सफल आपूर्ति कर राष्ट्रीय स्तर पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने इसे मजबूत ऊर्जा अवसंरचना, बेहतर प्रबंधन और सरकार की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम बताया। उनके अनुसार नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण, ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि, वितरण व्यवस्था के आधुनिकीकरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने से प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है।सदन की कार्यवाही के बाद मीडिया से बातचीत में ए.के. शर्मा ने कहा कि विपक्ष की जनहित के मुद्दों के प्रति नकारात्मक सोच और सरकार के विकास कार्यों में बाधा डालने की प्रवृत्ति पूरे प्रदेश ने देखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार नारेबाजी और व्यवधान के कारण सदन के तीन दिन का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ, जिससे प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ।उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि विपक्ष के लगातार विरोध के बावजूद सरकार ने सभी विधायी कार्य पूरे किए और अनुपूरक बजट भी पारित कराया।ए.के. शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ बहस, सार्थक संवाद और जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पूरे सत्र के दौरान विपक्ष ने केवल व्यवधान की राजनीति की। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और जनकल्याण के कार्यों के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से अपना निर्णय देगी।

रूफटॉप सौर ऊर्जा में उत्तर प्रदेश ने बनाया नया कीर्तिमान

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में अब तक लगभग 6.70 लाख रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता करीब 2,300 मेगावाट है। इसे स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रदेश की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।प्रदेश सरकार के अनुसार बढ़ती बिजली मांग को स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा से पूरा करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया गया है। पारदर्शी ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, सरल स्वीकृति प्रक्रिया, केंद्र और राज्य सरकार की अनुदान योजनाओं तथा तकनीकी सहयोग के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित किए हैं। इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी आने के साथ अतिरिक्त बिजली उत्पादन के माध्यम से आय के अवसर भी बढ़े हैं।राजधानी लखनऊ रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने में प्रदेश में सबसे आगे है। यहां 1.23 लाख से अधिक घरों में सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 426 मेगावाट है। इसके अलावा वाराणसी में लगभग 163 मेगावाट और कानपुर में 147 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे इन शहरों में भी स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को नई गति मिली है।विद्युत वितरण निगमों के क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार मध्यांचल विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में सर्वाधिक 931 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित हुए हैं। इसके बाद पूर्वांचल क्षेत्र में 502 मेगावाट, दक्षिणांचल में 340 मेगावाट और पश्चिमांचल में 311 मेगावाट क्षमता विकसित की जा चुकी है।

लोक एवं जनजातीय संस्कृति के संरक्षण को मिलेगी नई गति, वार्षिक कार्ययोजना को सामान्य परिषद की मंजूरी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान की सामान्य परिषद की बैठक बुधवार को संस्कृति निदेशालय के सभागार में विशेष सचिव संस्कृति दीपा रंजन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही प्रदेश की लोक एवं जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रचार-प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।बैठक में संस्थान के प्रशासनिक, वित्तीय और सांस्कृतिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। विभिन्न योजनाओं के प्रभावी संचालन, संसाधनों के बेहतर उपयोग, कार्यों में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुझावों पर चर्चा करते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन पर सहमति व्यक्त की गई।परिषद के सदस्यों ने प्रदेश की लोक एवं जनजातीय कला, लोक परंपराओं और लोक कलाकारों के संरक्षण तथा उनके प्रोत्साहन के लिए संचालित योजनाओं और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। बैठक में संस्थान की आगामी सांस्कृतिक गतिविधियों, शोध एवं प्रकाशन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़े विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई।अध्यक्ष दीपा रंजन ने संस्थान को प्रदेश की समृद्ध लोक एवं जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए अधिक सक्रिय, प्रभावी और परिणामोन्मुखी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने, संस्थान की गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने तथा विलुप्तप्राय लोक धरोहरों, पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजनों, लोक औषधीय ज्ञान और अन्य सांस्कृतिक परंपराओं का व्यवस्थित प्रलेखन, संरक्षण और संग्रहण करने पर बल दिया।बैठक में संस्कृति विभाग के अधीन संचालित सभी संस्थानों और अकादमियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन तथा प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।बैठक में भारतेन्दु नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, राज्य संग्रहालय, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, पुरातत्व विभाग सहित विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों और सामान्य परिषद के सदस्यों ने भाग लिया। अंत में संस्थान के निदेशक अतुल द्विवेदी ने सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

युवा पीढ़ी को विरासत से जोड़ने के लिए आयोजित हुआ शैक्षिक कार्यक्रम

लखनऊ। भारतीय संस्कृति और विरासत से युवा पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इतिहास संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित यूथ लीडरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय के सहयोग से निदेशालय सभागार में रेजिडेंसी, छतर मंजिल और फरहत बख्श पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालक एवं बालिका विद्यालय, मोहन रोड, लखनऊ तथा विद्याज्ञान स्कूल, सीतापुर के लगभग 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य पुरातत्व निदेशक रेनू द्विवेदी ने विद्यार्थियों से स्थानीय विरासत, संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्मारकों को निकट से जानने तथा उनके संरक्षण में सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपनी सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़कर ही नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ बना सकती है।

प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चलेगा ‘हर घर तिरंगा अभियान’, 5 करोड़ तिरंगे फहराने का लक्ष्य

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार 9 से 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ का आयोजन करेगी। अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए शासन ने सभी विभागों और जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला स्तर पर सभी कार्यक्रमों के संचालन और समन्वय की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारियों को सौंपी गई है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में 5 करोड़ तिरंगे फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति सम्मान की भावना को सशक्त करना है। उन्होंने कहा कि अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ जनआंदोलन के रूप में आयोजित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि अभियान का प्रथम चरण 6 से 8 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान विद्यालयों की दीवारों और सूचना पटों पर तिरंगे से प्रेरित चित्रकारी और कलाकृतियां बनाई जाएंगी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस अड्डों, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक उद्यानों तथा अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी।द्वितीय चरण 9 से 12 अगस्त तक आयोजित होगा। इस दौरान प्रत्येक जनपद के तकनीकी संस्थानों में स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

पीओके की पुकार और दुनिया की जिम्मेदारी

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में इन दिनों जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, वे केवल एक चुनावी प्रक्रिया की कहानी नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और जनविश्वास के गहरे संकट की दास्तान हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक शक्ति निष्पक्ष चुनाव, नागरिक स्वतंत्रता और शासन की जवाबदेही में निहित होती है, लेकिन जब चुनाव भय, हिंसा, प्रशासनिक दबाव और धांधली के आरोपों से घिर जाएँ, तब लोकतंत्र का स्वरूप विकृत हो जाता है। आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति इसी कठोर वास्तविकता की ओर संकेत करती है। वहाँ के लोगों का आक्रोश केवल चुनावी अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही आर्थिक उपेक्षा, राजनीतिक भेदभाव और नागरिक अधिकारों की अनदेखी के विरुद्ध भी है। यही कारण है कि वहाँ का असंतोष अब स्थानीय मुद्दा न रहकर अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बनता जा रहा है। लोकतंत्र केवल मतपेटियों तक सीमित नहीं होता। लोकतंत्र का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के अपनी इच्छा व्यक्त कर सके और उसकी अभिव्यक्ति का सम्मान हो। यदि किसी क्षेत्र में चुनाव पहले से तय परिणामों का माध्यम बन जाएँ, यदि सत्ता का पूरा तंत्र एक दल विशेष के पक्ष में खड़ा दिखाई दे, यदि विरोध की आवाज को बलपूर्वक दबाया जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, तो उसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में समय-समय पर ऐसे आरोप सामने आते रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सत्ता का प्रभाव प्रशासन और चुनावी व्यवस्था पर स्पष्ट दिखाई देता है। यदि जनता के मन में यह विश्वास ही समाप्त हो जाए कि उसका मत परिवर्तन ला सकता है, तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार ही समाप्त हो जाता है।

पाकिस्तान स्वयं को लोकतांत्रिक राष्ट्र कहता है, लेकिन उसके व्यवहार में लोकतंत्र की मूल भावना बार-बार प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव करवा देना नहीं है, बल्कि असहमति का सम्मान करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और सत्ता की आलोचना को स्वीकार करना भी है। यदि विरोध करने वालों को राष्ट्रविरोधी या व्यवस्था विरोधी बताकर दबाने का प्रयास किया जाए, यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाए और यदि प्रशासन जनता के बजाय सत्ता के हितों की रक्षा करता दिखाई दे, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की विश्वसनीयता स्वतः समाप्त होने लगती है। पाकिस्तान की यही दोहरी नीति आज उसके लोकतांत्रिक दावों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक भी है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद वहाँ का सामान्य नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। बिजली संकट, महँगाई, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं की कमी और विकास की धीमी गति ने जनजीवन को अत्यंत कठिन बना दिया है। यह विडंबना है कि जिन नदियों से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी क्षेत्र के लोग लंबे समय तक बिजली कटौती झेलने को विवश हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके संसाधनों का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन उनके विकास के लिए अपेक्षित निवेश नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में जनता के भीतर असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक है।

लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी कसौटी यह होती है कि वह संकट के समय जनता के साथ किस प्रकार खड़ा रहता है। यदि जनता की शिकायतों का समाधान संवाद से करने के बजाय दमन से किया जाए, तो यह शासन की कमजोरी का प्रमाण होता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों और असंतोष के प्रति जिस प्रकार का रवैया अपनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं, वे चिंता पैदा करते हैं। लोकतंत्र का उत्तर हिंसा नहीं, बल्कि संवाद होता है। दुर्भाग्य से जब शासन संवाद छोड़कर शक्ति प्रदर्शन का मार्ग अपनाता है, तब जनता और व्यवस्था के बीच विश्वास की खाई और गहरी हो जाती है। विश्व समुदाय के सामने भी यह एक गंभीर नैतिक प्रश्न है। यदि लोकतंत्र और मानवाधिकार वास्तव में सार्वभौमिक मूल्य हैं, तो उनका संरक्षण केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और महाशक्तियाँ अनेक अवसरों पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानवाधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा की बात करती हैं। यदि यही सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उठ रहे प्रश्नों की भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। मानवाधिकारों का मूल्य भौगोलिक सीमाओं से निर्धारित नहीं होता। जहाँ भी नागरिकों की स्वतंत्रता और सम्मान प्रभावित होता है, वहाँ वैश्विक समुदाय की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दे।

जन्म के पहले घंटे में जरूर कराएं स्तनपान, नवजात को बनाएं आयुष्मान

विश्व स्तनपान सप्ताह पर विशेष

मुकेश कुमार शर्मा

बीमारी की स्थिति में भी माँ बच्चे को पूरी सावधानी के साथ स्तनपान जरूर कराएं क्योंकि यह बच्चे को बीमारी से सुरक्षित बनाता है।

मां का पहला पीला गाढ़ा दूध यानि जन्म के पहले घंटे में स्तनपान नवजात के जीवन की नई शुरुआत का सबसे कारगर और प्रभावी तरीका है। यह जहाँ बच्चे को सम्पूर्ण पोषण प्रदान करता है वहीँ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा मां और बच्चे में एक जुड़ाव और लगाव भी पैदा करता है। इतने सारे गुणों से भरपूर स्तनपान को लेकर आज भी कई भ्रांतियां और मिथक भी मौजूद हैं, जिनको दूर करने के लिए हर साल एक से सात अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान अस्पतालों और समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर शीघ्र स्तनपान (जन्म के पहले घंटे) और छह माह तक सिर्फ स्तनपान को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। इस साल विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम "जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान-कारगर उपायों को सुदृढ़ बनाना" तय की गयी है। इसका उद्देश्य मां (खासकर कामकाजी महिलाओं) और बच्चे को एक ऐसा बेहतर माहौल प्रदान करना है, जिससे वह स्तनपान में किसी तरह की हिचक या संकोच न महसूस कर सकें।

मां का पहला पीला गाढ़ा दूध (कोलेस्ट्रम) को नवजात का पहला टीका भी माना जाता है, क्योंकि वह बच्चे को डायरिया, निमोनिया और कुपोषण समेत कई संक्रामक बीमारियों से महफूज बनाने के साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक साबित होता है। स्तनपान एक तरह से शिशु का मौलिक अधिकार भी है, इसलिए परिवार और कार्यस्थल की जिम्मेदारी बनती है कि वह महिला को एक ऐसा सुरक्षित माहौल प्रदान करें जहाँ पर वह बच्चे को आसानी से स्तनपान करा सके। इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि शिशु को छह माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना है क्योंकि बाहरी कोई भी चीज देने से उसके संक्रमण की चपेट में आने की पूरी संभावना रहती है। अमृत समान माँ के अनमोल दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्वस्थ वसा, विटामिन, खनिज और पानी का सही संतुलन होता है। जीवन के पहले छह माह के दौरान शिशु के विकास के लिए इन्हीं चीजों की सबसे अधिक जरूरत भी होती है। इसीलिए छह माह तक माँ अगर बच्चे को भरपूर स्तनपान कराती है तो ऊपर से पानी पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे की खुशहाली और दूध का बहाव अधिक रखने के लिए जरूरी है कि माँ प्रसन्नचित रहें और तनाव व चिंता से दूर रहें।

बीमारी की स्थिति में भी माँ बच्चे को पूरी सावधानी के साथ स्तनपान जरूर कराएं क्योंकि यह बच्चे को बीमारी से सुरक्षित बनाता है। स्तनपान से जुड़े कई मिथक भी हैं, जैसे-स्तनपान में कठिनाई या दूध का पूरी तरह से न बनना। जबकि ऐसा कतई नहीं है, यदि बच्चे को सही जुड़ाव और सही तरीके से स्तनपान कराया जाए तो यह समस्या नहीं आ सकती। ऐसा महसूस हो तो जरूर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से सम्पर्क कर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। इसके अलावा स्तन में दूध पर्याप्त मात्रा में बने इसके लिए जरूरी है कि माताएं अधिक से अधिक तरल पदार्थों और पोषक तत्वों को अपने भोजन में शामिल करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और फलों, हरी सब्जियों, साबुत अनाज, प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर संतुलित आहार को अपनाएं ताकि स्वस्थ रहें और दूध भी भरपूर मात्रा में बने।

केवल स्तनपान कर रहा शिशु 24 घंटे में छह से आठ बार पेशाब कर रहा है तो यह समझना चाहिए कि उसे भरपूर खुराक मिल रही है। इसके साथ ही स्तनपान के बाद बच्चा कम से कम दो घंटे की नींद ले रहा है और बच्चे का वजन हर माह 500 ग्राम बढ़ रहा है तो किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह प्रमाण है कि शिशु को भरपूर मात्रा में माँ का दूध मिल रहा है। नवजात को शीघ्र और नियमित स्तनपान कराने से जन्म के पश्चात बच्चेदानी के जल्दी सिकुड़ने, अधिक रक्तस्राव और एनीमिया से बचाव होता है। इसे एक कारगर गर्भनिरोधक के रूप में भी माना जाता है। मोटापा कम करने और शरीर को सुडौल बनाने में भी यह सहायक होता है। शिशु को स्तनपान कराने से स्तन और अंडाशय के कैंसर से भी बचाव होता है। कृत्रिम आहार या बोतल के दूध में पोषक तत्वों की मात्रा न के बराबर होती है। इसलिए यह बच्चे के पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे कुपोषण की जद में आने के साथ ही संक्रमण का जोखिम भी बना रहता है। बौद्धिक विकास को भी यह प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट भी बताती हैं कि छह माह तक लगातार शिशु को केवल स्तनपान कराने से 11 फीसदी दस्त रोग और 15 प्रतिशत निमोनिया के मामले को कम किया जा सकता है।

(लेखक पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं)

व्यंग्य

मुद्दे को दलगत रंग

मुद्दा संसदीय गतिरोध नहीं, बल्कि सड़कों पर खड़ा हो रहा गतिरोध है। सरकार को इसे समझने की संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। मुद्दे को दलगत दायरे में समेटने का नजरिया जोखिम भरा साबित हो सकता है।

मुद्दा शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रखने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को सौंपी। उधर अपनी प्रेस कांफ्रेंस में जेपी नड्डा ने कॉकरोच आंदोलन की मांगों पर चर्चा करने के बजाय संसदीय गतिरोध दूर करने के लिए विपक्ष के सामने प्रस्ताव रखा। कहा कि नीट और अन्य परीक्षाओं में 'वर्तमान एनडीए एवं पूर्व यूपीए सरकारों के दौरान हुई' पेपर लीक की घटनाओं पर सरकार संसद में पूरी चर्चा के लिए तैयार है। स्पष्टतः इस मुद्दे को उन्होंने दलगत रंग दिया। मतलब सरकार चाहती है कि सड़क पर उठ रहे सवालों को दरकिनार कर सत्ता पक्ष और विपक्ष पेपर लीक एवं परीक्षा व्यवस्था ध्वस्त के प्रश्नों पर आपसी तू तू-मैं मैं का साया डाल दें!

और अगर विपक्ष ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो संसदीय गतिरोध की जिम्मेदारी उसके माथे पर डाली जाए। बहरहाल, विपक्षी दल इतना तो शायद समझते ही हैं कि युवा मन की उथल-पुथल को नजरअंदाज करना उनके लिए अपनी प्रासंगिकता को दांव पर लगाना होगा। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया है कि कॉकरोच आंदोलन की इन तीन मांगों को मानना गतिरोध तोड़ने की पूर्व शर्त हैः शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र ' प्रदर्शनकारियों पर हुए 'जुल्म' की जवाबदेही तय की जाए, और प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगें।

देश में युवा असंतोष के इजहार से जिस तरह की सूरत बन रही है, सरकार के लिए इन मांगों को मान लेना बुद्धिमानी की बात होगी। 20 जुलाई को राजधानी में लाठी चार्ज, आंसू गैस और कथित रूप से पैलेट गन के इस्तेमाल की खबरों ने युवा आक्रोश को और भड़काया है। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों ने मरहम लगाने के बजाय विपरीत प्रतिक्रिया पैदा की है। ऐसे में मुख्य मुद्दा संसदीय गतिरोध नहीं, बल्कि सड़कों पर खड़ा हो रहा गतिरोध है। सरकार को इस स्थिति को समझने की संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। सड़क पर के गतिरोध का समाधान फिलहाल उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुद्दे को दलगत दायरे में समेटने का नजरिया जोखिम भरा साबित हो सकता है।

ब्लॉग

नक्सल-मुक्त भारतः एकीकृत रणनीतियों से वामपंथी उग्रवाद पर निर्णायक विजय

भारत ने वामपंथी उग्रवाद से लगभग पूरी तरह मुक्त होने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब देश का कोई भी जिला वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित नहीं है। यह परिवर्तन एक बहुआयामी और समन्वित रणनीति का परिणाम है, जिसमें सुरक्षा अभियान, बुनियादी ढांचे का विस्तार, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का पुनर्वास, आदिवासी कल्याण और सुशासन को समान

लगभग छह दशकों तक भारत वामपंथी उग्रवाद की चुनौती से जूझता रहा। यह केवल एक सुरक्षा समस्या नहीं थी, बल्कि लाखों आदिवासी परिवारों और उन गांवों के लिए रोज़मर्रा की कठोर वास्तविकता थी, जो लंबे समय तक सड़कों, स्कूलों व समावेशी विकास के अवसरों से वंचित रहे। लगातार होने वाली हिंसा ने इन क्षेत्रों में जीवन को अनिश्चितता और भय से घेर रखा था।

31 मार्च 2026 को इस स्थिति में एक ऐतिहासिक बदलाव आया और भारत की आंतरिक सुरक्षा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल हुआ। देश ने नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता प्राप्त की। मई 2014 में केंद्र सरकार के सत्ता में आने के समय रेड कॉरिडोर देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने मौजूद सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक था। पहले अपनाए गए उपाय काफी हद तक बिखरे हुए और घटनाओं पर आधारित थे। इनमें अक्सर समस्या की मूल वजहों को दूर करने के बजाय उसके तत्काल प्रभावों से निपटने पर अधिक जोर दिया जाता था। इसके बाद वामपंथी उग्रवाद की चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा, विकास, बुनियादी ढांचे, सुशासन और जनकल्याण को एक साथ जोड़ने वाली व्यापक एवं एकीकृत रणनीति अपनाई गई। इसी समन्वित दृष्टिकोण ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी बदलाव की नींव रखी।

पिछले बारह वर्षों में यह बदलाव तीन परस्पर जुड़े और एक-दूसरे को मजबूत करने वाले प्रयासों के माध्यम से आया। लोगों का विश्वास और भरोसा बहाल करने के लिए सुरक्षा अभियानों को सुदृढ़ किया गया, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास के लिए व्यवस्थित तंत्र विकसित किए गए तथा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तक लगातार पहुंच बनाई गई।

बुनियादी ढांचे के विस्तार के तहत भौतिक व डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया, दूर-दराज के क्षेत्रों तक प्रशासन की पहुंच बढ़ाई गई और दीर्घकालिक आर्थिक अवसरों का सृजन किया गया। वहीं, कल्याणकारी गतिविधियों में सम्मान, समावेशी सेवाओं की पहुंच, सांस्कृतिक समावेशन और प्रभावित समुदायों को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। इनमें से प्रत्येक प्रयास ने दूसरे प्रयासों को और मजबूत किया। सुरक्षा ने विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया, विकास ने लोगों का विश्वास गहरा किया और विश्वास ने कल्याणकारी पहलों को गति प्रदान की। यह कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं थी, जिसमें एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाया गया हो; बल्कि यह शांति, विकास एवं विश्वास को लगातार मजबूत करने वाली एक सशक्त और अविच्छिन्न कड़ी थी।

इस प्रयास का उद्देश्य संवेदनशील और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में सरकार की निरंतर उपस्थिति के माध्यम से लोगों का विश्वास और भरोसा बहाल करना था। प्रभावी व समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों तथा सरकारी संस्थाओं के बीच तालमेल को और मजबूत किया गया। इस समग्र दृष्टिकोण ने स्थानीय समुदायों और सरकारी तंत्र के बीच लंबे समय से बनी दूरी को कम करने तथा आपसी विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी विद्रोह से हुई। यह आंदोलन माओवादी विचारधारा और सशस्त्र क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था। इसका मूल विचार हिंसक क्रांति के माध्यम से सत्ता हासिल करना था। समय के साथ वामपंथी उग्रवाद का विस्तार कई क्षेत्रों में हुआ। उग्रवादी संगठनों ने हथियारों और संसाधनों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों तथा पुलिस शस्त्रागारों को भी निशाना बनाया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, नक्सलियों के लगभग 92 प्रतिशत हथियार पुलिस शस्त्रागारों से लूटे गए थे। वर्ष 2004 में कई उग्रवादी संगठनों के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) में विलय के बाद यह संगठन और अधिक संगठित एवं प्रभावशाली हुआ। इसके परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। साल 2004 से 2014 का दशक वामपंथी उग्रवाद के इतिहास में सबसे हिंसक दशकों में से एक था। हिंसा 2010 में अपने चरम पर थी, जब एक ही साल में 1,936 घटनाएं हुईं और 720 नागरिकों की मौत हुई। पूरे दशक में हिंसा की 17,542 घटनाएं हुईं, जिनमें सुरक्षा बलों के 1,913 जवान और 5,019 नागरिक मारे गए।

कोई एक जैसी राष्ट्रीय नीति नहीं थी। राज्य सरकारें अलग-अलग काम करती थीं। फिर भी, 2009 में सरकार ने सार्वजनिक रूप से माना कि नक्सलवाद भारत के सामने सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती है, जिसका दायरा कश्मीर और पूर्वोत्तर से भी कहीं ज़्यादा बड़ा था।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को मंजूरी मिलने के साथ वर्ष 2015 में एक निर्णायक कदम उठाया गया। इसके तहत पहले अपनाए जाने वाले कामचलाऊ और बिखरे हुए दृष्टिकोण की जगह एक व्यवस्थित, समन्वित और संपूर्ण सरकारी तंत्र को शामिल करने वाली रणनीति अपनाई गई। इस रणनीति के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती, विशेष प्रशिक्षण और सुरक्षा अभियानों को मजबूत करने के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद के सामाजिक-आर्थिक कारणों पर भी ध्यान दिया गया। इसके लिए सुरक्षा संबंधी व्यय, विशेष बुनियादी ढांचा योजना और विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) जैसी योजनाओं के माध्यम से आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए। 2017 में विशेष केंद्रीय सहायता योजना की शुरुआत के बाद से अब तक लगभग 4,289.20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इन गतिविधियों ने सुरक्षा उपायों के साथ-साथ विकास और जनकल्याण को गति देकर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी बदलाव की नींव मजबूत की। विशेष बुनियादी ढांचा योजना (एसआईएस) के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष बलों, विशेष खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस ढांचे को मजबूत करने तथा सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण के लिए 1,761 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

वर्ष 2014–15 से अब तक सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत 3,805.04 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षा बलों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं व प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करना, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के पुनर्वास में सहायता करना तथा शहीद सुरक्षा कर्मियों और हिंसा में मारे गए नागरिकों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करना है।

पहली बार, भारत ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बातचीत, सुरक्षा और समन्वय पर आधारित एक व्यवस्थित और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। गृह मंत्रालय के तहत अधिक केंद्रीकृत एवं समन्वित ढांचे के माध्यम से सरकारी प्रयासों को आगे बढ़ाया गया, जिससे नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और प्रभावित क्षेत्रों में कार्रवाई की गति को मजबूत किया जा सका।

भारत को नक्सलवाद के भय और हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य केंद्रित योजना, प्रभावी रणनीति और मजबूत आपसी समन्वय के माध्यम से हासिल किया गया। 24 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। सुरक्षा अभियानों में तेजी लाने, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने, बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए किए गए समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप यह लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर हासिल कर लिया गया। यह उपलब्धि सुरक्षा और विकास को साथ लेकर चलने वाली एकीकृत रणनीति की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

सरकार ने बुनियादी ढांचे के विस्तार, विशेष बलों और बेहतर ऑपरेशनल तालमेल के ज़रिए नक्सल-प्रभावित इलाकों में सुरक्षा की कमी को व्यवस्थित रूप से दूर किया। इस एकीकृत दृष्टिकोण ने रेड कॉरिडोर में राज्य की मौजूदगी, आवाजाही, खुफिया जानकारी साझा करने और उग्रवाद-विरोधी क्षमताओं को बढ़ाया। वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 66 सुदृढ़ पुलिस थाने थे, जबकि अब ऐसे 663 पुलिस थाने स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले सात वर्षों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने, क्षेत्रों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने और दूर-दराज़ के वन क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाने के लिए 408 नए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) सुरक्षा शिविर बनाए गए हैं। दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तेज़ी से तैनाती व आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 68 रात्रि-अवतरण हेलीपैड भी विकसित किए गए हैं। इनसे सैनिकों की आवाजाही, घायलों को सुरक्षित निकालने और निगरानी अभियानों में महत्वपूर्ण सहायता मिली है। सुरक्षा बलों की सुरक्षा और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 400 बुलेटप्रूफ एवं विस्फोटरोधी वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही, जवानों के कल्याण और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए 5 अस्पताल भी स्थापित किए गए हैं। इन उपायों ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को अधिक मजबूत, सक्षम और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक बहुस्तरीय और समन्वित सुरक्षा तंत्र विकसित किया गया, जिसमें कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रिज़ॉल्यूट एक्शन), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) तथा राज्यों की विशेषीकृत इकाइयों, जैसे झारखंड जगुआर, छत्तीसगढ़ पुलिस की विशेष इकाइयों और आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड्स, को एक साथ जोड़ा गया। डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा के बीच संयुक्त प्रशिक्षण और परिचालन समन्वय को बढ़ावा दिया गया। इससे एक ऐसी एकीकृत और तालमेल के साथ काम करने वाली सुरक्षा शक्ति विकसित हुई, जिसमें जिम्मेदारियों और कमान की स्पष्ट व्यवस्था थी। इस समन्वित मॉडल ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा अभियानों की प्रभावशीलता और परिचालन क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अवैध आरा मशीनों पर कार्रवाई या दिखावा

बल्दीराय/सुल्तानपुर। धनपतगंज क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चार अवैध आरा मशीनों पर छापेमारी कर उपकरण जब्त किए गए तथा संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। विभाग की इस कार्रवाई को अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने की पहल बताया जा रहा है, लेकिन इस कार्रवाई ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर कई और गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। धनपतगंज में आरा मशीनों पर हुई कार्यवाई तो बल्दीराय क्षेत्र और हलियापुर क्षेत्र के आरा मशीनों को बरदान क्यों ? बल्दीराय और हलियापुर के आसपास के क्षेत्रों में वर्षों से संचालित अनेक आरा मशीनों पर प्रतिबंधित प्रजातियों की लकड़ियां, विशेषकर आम, महुआ तथा अन्य मूल्यवान वृक्षों की लकड़ी खुलेआम देखी जाती रही है। यदि शासन के नियमों के अनुसार इन पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध है और बिना अनुमति कटान अपराध की श्रेणी में आता है।

सिर और गर्दन की हड्डियां चबाईं, फाड़ दिया पेट और सीना, तेंदुए ने संतोष के चेहरे का मांस भी नोच-नोचकर खाया

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। ले में मारी गई संतोष का दो डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। तेंदुए ने संतोष के सिर और गर्दन की हड्डियां चबा लीं थीं। चेहरे का मांस भी नोच-नोचकर खाया। सीना और पेट तो पूरी तरह से फाड़ दिया था। हाथ और कंधे से भी मांस नोचा है। मंगलवार को जारी हुई लालापुर पीपलसाना निवासी संतोष के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है। ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के लालापुर पीपलसाना गांव निवासी संतोष देवी (45) पर सोमवार की दोपहर को तेंदुए ने उस वक्त हमला कर दिया था जब वह गन्ने के खेत में काम कर रही थी।

मां को बुलाने खेत पर पहुंची रविता ने देखा कि तेंदुए ने उसकी मां की गर्दन पकड़ रखी है और खेत के भीतर ले जा रहा है। रविता ने शोर मचा दिया। आसपास के लोग पहुंचे और तेंदुए को घेरने की कोशिश की लेकिन वह शव छोड़कर भाग गया था।

तेंदुए ने पूरी तरह से खा लिया था चेहरा

तेंदुए ने संतोष का सिर और चेहरा खा लिया था। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चेहरा पूरी तरह से खा लिया था। सिर की हड्डियां तक चबा लीं। गर्दन की कई हड्डियां तो गायब मिलीं हैं। पेट और सीने का भी मांस खा लिया है।

पुलिस अधीक्षक देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। तेंदुए की तलाश में वन विभाग टीम जुटी है। ड्रोन और अन्य संसाधनों के जरिये तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पिंजरे और जाल भी लगाए गए हैं।

संतोष पर तेंदुए का हमला

मुरादाबाद के लालापुर पीपलसाना गांव के जंगल में सोमवार की सुबह खेत में पशुओं के हरे चारे के लिए गन्ने की पत्ती उतार रही महिला संतोष देवी (45) पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए ने महिला का सिर और चेहरा खा लिया। सीने से भी मांस नोचा है। मां को बुलाने खेत पर गई बेटी ने तेंदुए को देखा तो शोर मचा दिया।

आसपास के ग्रामीण मौके की तरफ दौड़े तो तेंदुआ शव छोड़कर भाग गया। पुलिस और वन विभाग के अफसरों का कहना है कि तेंदुए ने महिला का सिर और चेहरा खा लिया है। शरीर के दूसरे हिस्सों से भी मांस नोचा है। वहीं इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम के लिए शव नहीं उठने दिया। लोगों ने तेंदुए को पकड़ने और महिला के परिजनों को आर्थिक मदद की मांग की। मौके पर पहुंचे एसडीएम अभिषेक कुमार सिंह ने लोगों को हर मदद करने का आश्वासन देकर शांत किया। एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि लालापुर पीपलसाना गांव निवासी वीरेंद्र सिंह सैनी की पत्नी संतोष देवी सोमवार की सुबह करीब नौ बजे अपने खेत में पशुओं के लिए गन्ने से पत्ती उतारने गईं थीं।

खेत के बीच में जाकर वह हरी पत्ती उतार रहीं थीं। इसी दौरान खेत में छिपे तेंदुए ने महिला पर पीछे से हमला कर दिया। हल्ला तब मचा जब संतोष देवी की बेटी रविता अपनी मां को बुलाने करीब साढ़े बारह बजे खेत पर गई। रविता ने जो बताया उसके मुताबिक जब वह खेत पर पहुंची तो तेंदुआ उसकी मां के ऊपर बैठा था और मांस नोच रहा था।

वह वहां से भागी और शोर मचा दिया। शोर-शराबा सुनकर आसपास के खेतों पर काम कर रहे ग्रामीण मौके पर आ गए। तेंदुए को घेरने की भी कोशिश की लेकिन वह भाग गया। कुछ ही देर में यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। इन लोगों ने घटना को लेकर नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

शव भी नहीं उठने दिया। किसी तरह पुलिस शव को पिकअप में रखकर जब गांव में पहुंची तो ग्रामीणों ने पिकअप को रोक लिया। परिवार को आर्थिक मदद और तेंदुए को पकड़ने की मांग गूंजने लगी। मौके पर पहुंचे एसडीएम अभिषेक कुमार सिंह ने ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा देकर शांत किया।

सपा के बैनर तले हुआ निषाद महासम्मेलन

सुलतानपुर। लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाबा भूतनाथ धाम, धनहुआ मुरारचक में श्रीकांत निषाद के नेतृत्व में निषाद जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में निषाद समाज के लोगों एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक जागरूकता का संदेश दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लम्भुआ विधानसभा के संभावित प्रत्याशी शिक्षक श्यामलाल निषाद गुरूजी ने अपने संबोधन में कहा कि दूसरों को पार लगाने वाले निषाद समाज के विकास की नाव आज भंवर में फंसी हुई है। समाज को सही दिशा और उसका अधिकार दिलाने के लिए चुनावी राजनीति की पतवार थामी है। कार्यक्रम की अजय निषाद की अध्यक्षता एवं देवमणि निषाद के संरक्षण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

विधायक व महिला के प्रकरण में नया मोड़, दोनो तरफ से ऑडियो वार हुआ शुरू

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। जिले के चर्चित विधायक व महिला विवाद में नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष के समर्थकों द्वारा ऑडियो वार करके एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि विधायक पुत्र भी अब इस मामले में कूद पड़े है। उन्होंने बाहुबली भाइयों को सीधे चुनौती देते हुए कानूनी कार्यवाही की बात कही है।

बता दे कि जिले की राजनीति में उस समय तूफान आ गया। जब दिल्ली में बैठक एक महिला ने 11 मिनट का वीडियो जारी कर शहर विधायक विनोद सिंह पर आरोपों की झड़ी लगा दी। महिला द्वारा विधायक पर दुष्कर्म के प्रयास की कोशिश सहित बेटी व परिवार पर हमले की आशंका का भी आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विधायक प्रतिनिधियों ने महिला सोनिया पांडेय व उसके पति शशांक पांडेय के खिलाफ विधायक हजरतगंज थाने में जालसाजी का आरोप लगाकर 10 जुलाई को दर्ज कराए गए मुकदमे की एफआईआर के साथ प्रेस नोट जारी किया। जिसमे विधायक पक्ष द्वारा वेयर हाउस के नाम पर फ्राड करने का आरोप लगाया गया है। मामला यही नहीं रुका फिर महिला सोनिया पांडेय के पति और विधायक विनोद सिंह का पुराना एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसमे विधायक द्वारा शशांक से पत्नी से बात कराने के लिए कहा जा रहा है। इस ऑडियो के वायरल होते ही पूरे मामले में विधायक विनोद सिंह के पुत्र पुलकित सिंह भी कूद पड़े और उन्होंने कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट को टैग करते हुए लिखा कि यह पोस्ट सोनू-मोनू के लिए है जो अक्सर सुल्तानपुर के अपराधिक गतिविधियों में पाए जाते है। आपके समर्थकों द्वारा विधायक विनोद सिंह का जो ऑडियो वायरल किया जा रहा है ये रिकॉर्डिंग उन्हें कहा से मिली। इसी के साथ उन्होंने बीएनएस की कुछ धाराओं का जिक्र करते हुए अपनी पोस्ट को समाप्त किया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ उसके बाद विधायक पक्ष द्वारा केएनआई के कर्मचारी अनिल सिंह व शशांक पांडेय के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल करवाया। जिसमे अनिल सिंह द्वारा वेयर हाउस के संबंध में बात की गई है तो शशांक द्वारा वेयर हाउस के कागजात की कुछ समय में पुष्टि हो जाने के साथ ही परिवार पर विधायक के गुर्गों से खतरे की आशंका जताई है। अब सोशल मीडिया पर छिड़े इस महासंग्राम से साफ हो चुका है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के करीब काफी दिनों से थे। हालांकि पूरे मामले में सच्चाई क्या है अभी यह भविष्य के गर्त में है। क्योंकि महिला द्वारा भी विधायक पर आरोप तब लगाया गया जब उसे विधायक द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में हाइकोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली।

जनगणना कर्मियों को नहीं मिला मानदेय, 31 जुलाई की समय-सीमा बीती

सुलतानपुर। भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आदेश के बावजूद जनपद की बल्दीराय तहसील में जनगणना-2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण का कार्य पूर्ण कर चुके प्रगणकों और सुपरवाइजरों को अब तक मानदेय का भुगतान नहीं हो सका है। निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा आईएएस ने 27 जुलाई 2026 को जारी पत्र में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि जनगणना कर्मियों के मानदेय एवं अन्य देयकों का भुगतान विलंबतम 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में कर दिया जाए। लेकिन बल्दीराय तहसील क्षेत्र में यह आदेश कागजों तक ही सीमित रह गया। यहां जनगणना के फील्ड वर्क में लगे सैकड़ों प्रगणक और सुपरवाइजर पिछले कई महीनों से मानदेय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जनगणना से जुड़ा क्षेत्रीय कार्य, घर-घर सर्वे और आंकड़ा संग्रह का काम समय पर पूरा कर लिया गया।

शामली में एक लाख का इनामी फुरकान मुठभेड़ में ढेर, कैराना पलायन मामले में भी था आरोपी

आर्यावर्त संवाददात

शामली। शामली जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कैराना निवासी एक लाख रुपये के इनामी बदमाश फुरकान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। फुरकान कुख्यात मुकीम काला गिरोह का सक्रिय सदस्य था और कैराना पलायन प्रकरण का मुख्य आरोपी माना जाता था। उसके खिलाफ हत्या, गैंगस्टर, रंगदारी सहित 20 से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे।

पुलिस को बुधवार दोपहर मुखबिर से सूचना मिली कि फुरकान झिंझाना क्षेत्र के गांव रंगाना के जंगल में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर दी। पुलिस को देखते ही फुरकान ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में फुरकान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

फुरकान पिछले लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वह कैराना क्षेत्र में अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात था। विशेष रूप से, कैराना से हुए पलायन के मामले में उसका नाम प्रमुखता से सामने आया था। इसके अलावा, वह मुकीम काला जैसे खूंखार गैंगस्टर के गिरोह से जुड़ा था, जिसकी वजह से उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि और भी गंभीर हो जाती है।

20 से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज

पुलिस के अनुसार, फुरकान के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलना और गैंगस्टर एक्ट के तहत 20 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश बना रही थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देने में सफल रहा था। उसकी आपराधिक गतिविधियों ने क्षेत्र में भय का माहौल बना रखा था। मुकीम काला गैंग के सदस्य शामली के साथ ही मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में भी सक्रिय हैं।

पुलिस की कार्रवाई और भविष्य

इस एनकाउंटर को पुलिस की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फुरकान जैसे अपराधियों का अंत कानून के शासन को मजबूत करता है। पुलिस आगे भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगी ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके।

फुरकान ने दिनदहाड़े की थी व्यापारी नेता विनोद सिंघल की हत्या

एसपी एनपी सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश फुरकान निवासी मोहल्ला आर्यपुरी कस्बा कैराना मारा गया। फुरकान ने 2014 में कस्बा कैराना में व्यापारी नेता विनोद सिंघल की रंगदारी न देने पर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद कैराना में दहशत बनने के बाद व्यापारियों ने पलायन करना शुरू कर दिया था।

हयात नगर में अमारी का जुलूस बहुत कामयाब रहा

सुलतानपुर। अंजुमन असगरिया वक्फ इमाम बाड़ा हयातनगर में बुधवार को जुलूस ए अरबईन का आयोजन किया गया। जिसमें सबसे पहले पेश ख्वानी जनाब डाक्टर रजी जाफर मेंहदी व आबिस रजा सुल्तानी ने किया और मजलिस अली हैदर आब्दी नेपढी इसके बाद अमारी का जुलूस उठकर करबला पर समाप्त हुआ। दौरान ए जुलूस अंजुमन सज्जा दिया जलालपुर अब्बासिया सुरौली अब्बासिया फरहत नगर फैजाबाद अजाए हुसैन सूरौली नौजवानाने हुसैनी आजम गढ़ व जाफरिया हयात नगर कोटवा ने नौहा मातम किया। संचालन जनाब कसीम आजमी ने किया इससे पूर्व सोमवार को मजलिस हुई जिसको मौलाना महताब अब्बास नजफी व मंगलवार को मौलाना शेर हैदर ने मजलिस पढी उक्त प्रोग्राम में अली रिजवान राना हसन अब्दुल कासिम कायम मेंहदी चांद भी मौजूद रहे इसकी जानकारी हैदर अब्बास खान अध्यक्ष हुसैनी शिया वेलफेयर एसोसिएशन सुल्तानपुर ने दी है।

एक्सप्रेसवे धंसने के मामले में NHAI की बड़ी कार्रवाई, पीएनसी इंफ्राटेक को नोटिस जारी

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए धंसाव के मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। परियोजना के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने पर रियायतग्राही, स्वतंत्र अभियंता और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही, जब तक एक्सप्रेसवे की पूरी मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक यात्रियों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। एनएचएआई के मुताबिक, बीते 26 जुलाई 2026 को एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 64 के पास सड़क में धंसाव (स्लिपेज) देखा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राधिकरण ने तुरंत बहाली का काम शुरू कराया और यातायात को सुरक्षित डायवर्ट कर दिया, जिससे आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है। स्थल के व्यापक तकनीकी परीक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं।

पीएनसी इंफ्राटेक को नॉन-परफॉर्मर घोषित करने का प्रस्ताव

प्रोजेक्ट की निर्माण एजेंसी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन-परफॉर्मर घोषित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत कंपनी भविष्य की एनएचएआई परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा कंपनी को निम्नलिखित मामलों में कारण बताओ नोटिस मिला है।

खुद के खर्चे पर करेगी मरम्मत

एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित हिस्से को ठीक करने में आने वाला करीब तीन करोड़ का पूरा खर्च रियायतग्राही कंपनी अपने खुद के संसाधनों से उठाएगी, जिससे सरकारी खजाने पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। सुधार कार्य पूरा होने तक टोल संग्रहण पूरी तरह स्थगित रहेगा और टोल राजस्व की भरपाई भी इसी कंपनी से की जाएगी।

सौंदरीकरण के नाम पर 9 करोड़ खर्च फिर भी परिसर तालाब में तब्दील

सुलतानपुर। कृषि उत्पादन मंडी समिति अमहट में सुंदरीकरण के नाम पर 9 करोड़ रूपये खर्च फिर भी बरसात में मंडी कैंम्पस व कार्यालय तालाब में तब्दील सौंदरीकरण पर किसानों व अढतियों ने उठाए सवाल, कृषि उत्पादन मंडी समिति अमहट में सौंदरीकरण के नाम पर लगभग लगभग 9 करोड़ रुपये मंडी निर्माण इकाई द्वारा खर्च किया जा चुका है सौंदरीकरण को लेकर अढतियो व किसानों ने सौंदर्य कार्य पर उठाए सवाल। मंडी के आढतियों व किसानों का आरोप है कि नाली का निर्माण अपेक्षाकृत न होने से पानी निकासी न होने के कारण हलकी बरसात होने से मंडी परिसर तालाब में तब्दील हो जाता है। वही आए दिन मंडी परिसर की बजबजाती नालिया। मंडी मे आढतियो के बीच असंवैधानिक रूप से चुनाव करके स्वयं मंडी समिति का अध्यक्ष घोषित करने वाले स्वंम ही मंडी समिति के लाखो के मंडी शुल्क के है

संक्षेप

जहरीले जंतु के काटने से महिला की मौत, मचा कोहराम

कुड़वार/सुल्तानपुर। सुबह पशुओं को चारा देने गई अधेड़ महिला को जहरीले जंतु ने काट लिया। गंभीर हालत में परिजन लेकर जिला मेडिकल कालेज पहुंचे। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। परिजनो की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने विधिक कार्यवाही की। बुधवार को स्थानीय थाना क्षेत्र सोहगौली गांव निवासी केश कुमारी(50) पत्नी राम करन यादव हर दिन की तरह पशुओं को चारा देने गई। जहां उन्हें किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। हालत गंभीर होने के बाद परिजन लेकर जिला मेडिकल कॉलेज गए।जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतक घोषित होने के बाद परिजन शव लेकर अपने घर चले आए। जिसकी सूचना परिजनो ने स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतका की तीनों बेटियों राजकुमारी, लालजी व कमला की शादी हो चुकी है। जबकि बेटे अमित यादव व राम विशाल यादव अविवाहित है। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। राजस्व निरीक्षक शिव प्रसाद ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है क्षेत्रीय लेखपाल से रिपोर्ट मंगाई गई है। जिससे परिवार को सांत्वना राशि दिलाई जा सके। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि सूचना पर शव का पंचनामा करके मर्चरी भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

मन्दिर परिसर में गुटका थूकने का किया विरोध तो रॉड से हुआ हमला

सुल्तानपुर। मन्दिर परिसर में गुटका थूकने का विरोध करना पड़ा भारी। एक हफ्ते बाद घात लगाकर हुआ हमला। घटना में युवक की कई हड्डियां टूट गईं। मामले में चोटहिल युवक की पत्नी ने कोतवाली देहात थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है। हालांकि सूत्र बता रहे कि किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नही हुई है। आपको बता दें कि घायल युवक अनुराग वर्मा के छोटे भाई एडवोकेट अशोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं। जिसको लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी घटना को लेकर मंडल उपाध्यक्ष से सहानुभूति जाहिर की है। जानकारी कं अनुसार अहिमाने ग्राम निवासिनी वादिनी रोशनी वर्मा के मुताबिक एक सप्ताह पूर्व काली माता के मंदिर के पास जितेन्द्र वर्मा (बाबा) सुत राम बरन वर्मा अपने तीन जुवारी साथियों के साथ बैठ कर ताश खेल रहा था और वहीं पर गुटका खा कर थूक रहा था। मंदिर की देख रेख करने वाले राम देव वर्मा ने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकी दी जाने लगी। प्रार्थिनी के पति अनुराग वर्मा ने पुजारी जी की बात का समर्थन किया और मंदिर स्थान पर गुटखा थूकने से मना किया तो उपरोक्त चारो लोग आमादा फौजदारी हो गए। आस-पास के लोगो के इकट्ठा हो जाने पर बात खत्म हुई। उसी रात प्रार्थिनी के पति दर्शन करने हेतु बाहर चले गए थे और कल रात लौट कर आए।बुधवार चार अगस्त को समय लगभग 2.30 बजे के आस-पास प्रार्थिनी के पति काली माता के स्थान के पास बैठे थे। तभी पीछे से विपक्षी जितेन्द्र वर्मा/बाबा सुत राम बरन वर्मा ने प्रार्थिनी के पति पर राड से हमला कर दिया। बहुत बुरी तरह मारा पीटा।

छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियां तेज, बैठक कर कांग्रेस ने बनाई रणनीति

सुल्तानपुर। आगामी 8 अगस्त को प्रयागराज के के.पी. ग्राउंड में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगमन को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने की। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, संगठनात्मक जिम्मेदारियों, जनसंपर्क अभियान तथा जिले से अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं, छात्र-युवाओं एवं आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न ब्लॉकों, नगर इकाइयों एवं न्याय पंचायत स्तर पर जिम्मेदारियां तय करते हुए सभी पदाधिकारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए।

लड़की एक, दोस्त तीन, दारू पार्टी और चैटिंग, इसलिए दोस्त ने हिस्ट्रीशीटर को क्रूरता से मारा, फोड़ दीं आंखें

आर्यावर्त संवाददाता

बांदा। बांदा में हिस्ट्रीशीटर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेमिका से चैट करने से बौखलाए जिगरी दोस्त ने ही हिस्ट्रीशीटर की हत्या की थी। पुलिस के अनुसार, तीन दोस्त शराब पी रहे थे। नशे में हिस्ट्रीशीटर ने आरोपी दोस्त को उसकी प्रेमिका की चैट अपने मोबाइल में दिखा दी थी, अवैध संबंध की भी बात कही।

इसी से गुस्साए आरोपी ने साथी के साथ मिलकर ईंट और डंडे से उसका चेहरा कूंचकर मार दिया। पुलिस ने आरोपी प्रधान के मौसेरे भाई सागर व उसके मित्र संजू को गिरफ्तार किया है। इस मामले का खुलासा दोनों हत्यारोपियों ने मंगलवार को पुलिस के सामने किया है।

पुलिस ने घटनास्थल से आला कत्ल ईंट और डंडा बरामद कर लिया है। उधर, पोस्टमार्टम में हिस्ट्रीशीटर के पूरे चेहरे में 10 चोटें पाई गईं। आंखें भी फोड़ दी गईं थीं। मटौंध थाना क्षेत्र के गांव दुरेड़ी में तिंदवारी के गांव अमलीकौर के दामिनताला निवासी धर्मेंद्र सिंह (40) की गांव के प्रधान के निर्माणाधीन मकान के पास ईंट व डंडे से कूंचकर सोमवार की रात करीब नौ बजे हत्या कर दी गई थी। इसके लिए पुलिस ने आरोपी दुरेड़ी गांव निवासी प्रधान के मौसेरे भाई सागर व उसके मित्र संजू को गिरफ्तार किया है। आरोपी सागर ने पुलिस को बताया कि धर्मेंद्र मौरंग डंप का व्यवसाय करता था। सागर की तीन माह से उसकी काफी घनिष्ठता हो गई थी। धर्मेंद्र चरित्र का अच्छा नहीं था।

हिस्ट्रीशीटर के कई महिलाओं से थे संबंध

उसके कई महिलाओं से संबंध थे। आरोप है कि धर्मेंद्र उसकी प्रेमिका पर भी गंदी निगाह रखने लगा था। उसने रात में शराब के नशे में यह बात बताई तो वह आपे से बाहर हो गया और धर्मेंद्र को मार डाला। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के समय सात लोग मौजूद थे।

सातों ने मिलकर शराब पी थी। शराब पीने के बाद चार लोग मौके से चले गए थे। मौके पर सिर्फ धर्मेंद्र, हत्यारोपी दुरेड़ी गांव का सागर और उसका साथी संजू ही मौके पर थे। शराब के नशे में सागर की महिला मित्र के विषय में कहने पर झगड़ा हुआ और हत्या की वारदात हुई।

हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र की हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ईंट व डंडा भी बरामद किया है। घटना में झगड़े की मुख्य वजह आरोपी की महिला मित्र से बातचीत करना सामने आया है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।- पलाश बंसल, पुलिस अधीक्षक, बांदा

पिता थे मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल

हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र (40) के चचेरे भतीजे दशरथ सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र के पिता राजकुमार सिंह की दो साल पहले निधन हो गया था। वह मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात थे। गांव में धर्मेंद्र की मां सरस्वती देवी व छोटा भाई मुलायम रहता है। सबसे बड़े भाई विजय सिंह की 20 साल पहले निधन हो चुका है।

धर्मेंद्र ने वर्ष 2007 में अमलीकौर निवासी द्वारिका सिंह की हत्या कर दी थी। बाद में उसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हुई थी। परिजनों का दावा है कि वह हत्या के मामले में बरी हो चुका था। बताया कि उसके चाचा हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं। पहली पत्नी रोशनी सिंह ने पांच साल पहले उससे संपर्क तोड़ लिया था। वह अपने पिता के साथ बांदा शहर के कालूकुआं मोहल्ले में रहती हैं। उनके एक बेटा व एक बेटी है। उसके बाद धर्मेंद्र ने एक विवाहित महिला रिंकी से शादी कर ली थी, वह बांदा के बाबूलाल चौराहे में किराये से रहती है। रिंकी के पहले पति से दो बेटे हैं।

वारदात से पहले पत्नी को की थी वीडियो कॉल

धर्मेंद्र (40) के छोटे भाई मुलायम ने मटौंध में दी तहरीर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई धर्मेंद्र ने कुछ दिन पहले बताया था कि सागर उससे रंजिश मानने लगा है। धर्मेंद्र जब अपनी भतीजी को लिवाने कबरई जा रहा था तो रास्ते में सागर ने उसे पकड़ लिया। इस पर शाम साढ़े पांच बजे करीब जब भाभी ने फोन किया तो धर्मेंद्र ने भाभी को वीडियो कॉल करके सागर के साथ होना बताया था।

घर पर सजाएं ये 5 तरह की मूर्तियां, खुल जाएंगे किस्मत के ताले

वास्तु शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति की तरक्की से लेकर उसके स्वास्थ्य, रिश्ते तक पर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसी कारण घर में ऐसी चीजों को रखा जाता है जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी अधिक पैदा हो। वास्तु शास्त्र में ऐसी ही कुछ ऐसी ही मूर्तियों के बारे में बताया गया है। सजावट के रूप में इस्तेमाल होने वाली ये मूर्तियां व्यक्ति की किस्मत को चमका सकतीहैं। जानिए वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कौन सी मूर्ति रखने से मिलेगा ढेरों लाभ।

सुख-समृद्धि के लिए घर लाएं ये मूर्ति

हाथी की मूर्ति

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में ठोस चांदी या फिर पीतल की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। क्योंकि हाथी को ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। इसके साथ ही धन लाभ के नए मार्ग खुलते है। वहीं बेडरूम में हाथी की मूर्ति रखने से वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है।

घोड़े की मूर्ति

घोड़े की मूर्ति घर में रखने से सफलता और ताकत मिलती है। घर की उत्तर दिशा में घोड़े की मूर्ति लगाने से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। नौकरी- बिजनेस में भी अपार सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही घर-परिवार में खुशियां बनी रहती है।

हंस की मूर्ति

हंस के जोड़े को घर में रखने से सुख-समृद्धि आती है। इसलिए घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सद्भावना में बढ़ोतरी होती है।

कछुआ

उन्नति और धन समृद्धि के लिए घर में कछुआ की मूर्ति रखनी चाहिए। ऐसा करने से उस घर में रहने वाले व्यक्ति की आयु भी बढ़ जाती है। घर की पूर्व और उत्तर दिशा में कछुआ रखना सबसे अच्छा है।

गाय बछड़े की मूर्ति

गाय की मूर्ति ऐसी लानी चाहिए जिसमें बछड़ा भी बना हुआ है। पीतल से बनी ऐसी मूर्ति घर में रखने से मानसिक शांति आती है। इसके साथ ही बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है।

इस बेहद लाभकारी जूस से ब्लड शुगर-कोलेस्ट्रॉल दोनों रहता है कंट्रोल, पाचन समस्याओं का रामबाण इलाज

एलोवेरा के पौधे को वर्षों से कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है। आयुर्वेद और मेडिकल साइंस दोनों में इससे होने वाले फायदों का जिक्र मिलता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नियमित रूप से एलोवेरा जूस पीने की सलाह देते हैं, पाचन से लेकर डायबिटीज की समस्या तक में इससे लाभ देखे गए हैं। एलोवेरा में कई प्रकार के प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो क्रोनिक बीमारियों के खतरे को कम करने से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा समस्याओं तक में आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इस जूस में विटामिन-सी की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है जिससे संक्रमण का जोखिम कम होता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी लाभ पहुंचता है।

नियमित रूप से सुबह एलोवेरा जूस के सेवन की आदत बनाएं। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उनके लिए यह आदत और भी लाभकारी हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, पौधे से ताजा जूस निकालकर उसका सेवन करना सबसे बेहतर माना जाता है। इसके सेवन के कई लाभ हो सकते हैं। आइए एलोवेरा जूस से सेहत को होने वाले गजब के फायदों के बारे में आगे विस्तार से जानते हैं।

पाचन से संबंधित कई तरह की समस्याओं में एलोवेरा जूस के सेवन के लाभ देखे गए हैं। अध्ययन में पाया गया है कि एलोवेरा जूस में एन्थ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड नामक तत्व होता है जो लैक्सेटिव प्रभावों के लिए जाना जाता है। एलोवेरा जूस का सेवन कब्ज को दूर करने और मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाने में विशेष लाभकारी हो सकता है। कुछ प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि एलोवेरा, गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (जीईआरडी) के लक्षणों को कम करने और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या में भी फायदेमंद है।

कोलेस्ट्रॉल भी रहता है कंट्रोल

एक अध्ययन से पता चला है कि एलोवेरा का जूस रक्त शर्करा को कम करने के साथ कोलेस्ट्रॉल की समस्या में भी फायदेमंद हो सकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन (एलडीएल) को भी यह कम कर सकता है। ये सभी हृदय रोगों के कारक माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि एलोवेरा के नियमित सेवन की आदत मौजूदा समय की दो सबसे बड़ी समस्याओं हृदय रोग और मधुमेह में लाभकारी है।

त्वचा विकारों में भी एलोवेरा से मिलता है लाभ

एलोवेरा को इसके एंटी-इंफ्लामेटरी प्रभावों के लिए जाना जाता है, जिससे यह जलन और अन्य त्वचा विकारों के लिए एक संभावित और प्रभावी उपचार हो सकता है। एलोवेरा जूस के सेवन के साथ इसे त्वचा पर लगाने को भी अध्ययनों में फायदेमंद पाया गया है। एक अध्ययन में 46 वर्ष से कम आयु के पुरुषों के समूह में 12 सप्ताह तक प्रतिदिन ऐलोवेरा के इस्तेमाल को त्वचा की लोच में सुधार करने और रंगत को ठीक रखने में भी लाभकारी पाया गया है।

डायबिटीज रोगियों को करना चाहिए इसका सेवन

डायबिटीज के शिकार लोगों के लिए भी एलोवेरा जूस फायदेमंद माना जाता है। जर्नल ऑफ़ क्लिनिकल फ़ार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, एलोवेरा प्री-डायबिटीज और टाइप-2 डायबिटीज वाले लोगों में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकता है। 470 प्रतिभागियों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि एलोवेरा जूस का सेवन करने से फास्टिंग ब्लड शुगर के स्तर को कम किया जा सकता है। डायबिटीज में पाचन की दिक्कत होना भी सामान्य है, जिसमें भी इसके

घर में लाते ही सेब खराब होने लगते हैं तो इस तरह से करें स्टोर

जब भी घर में सेब आते हैं तो वो दूसरे ही दिन से खराब होने लगते हैं। इससे बचने के लिए सेब को फ्रिज में डाल दिया जाता है। लेकिन फ्रिज में सेब भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं और स्वाद भी खराब हो जाता है। दरअसल, ऐसा सेब के साथ ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया की वजह से होता है। सेब को जब फ्रिज में रखा जाता है। तापमान की कमी की वजह से उसके एंजाइम्स ज्यादा तेजी के काम करने लगते हैं। जिससे सेब पक जाते हैं और स्वाद भी खऱाब हो जाता है। इसलिए जरूरी है ये जानना कि सेब को आखिर घर लाने के बाद कैसे रखें।

वहीं सवाल ये भी है कि क्या सेब को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं। फ्रिज का तापमान अगर काफी कम है तो सेब खराब हो सकता है। क्योंकि कई बार लोग सेब को खुला ही फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में अगर सेब रखना चाहती हैं तो इसे किसी प्लास्टिक या कागज में लपेट दें। ऐसा करने से सेब का एथिलीन तेजी से नहीं बढ़ेगा और सेब खराब नहीं होंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रहे कि सेब को काटकर या खुला ही लंबे समय तक ना रखें।

कैसे करें सेब में स्टोर

फ्रिज में सेब को तभी रखें जब उसकी मात्रा कम हो। साथ ही सेब को रखने से पहले फ्रिज का तापमान सामान्य रखें। बहुत अधिक कम तापमान की जरूरत सेब को नहीं होती। साथ ही इसमे ह्यूमिडिटी पूरे 90-95 प्रतिशत हो। पहले सेब को किसी प्लास्टिक की थैली में ऱखें। जिसमे छेद हो और एयर आसानी से निकल रही हो। अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रही तो सेब को किसी काजग में लपेटें और नीचे बनीं बॉस्केट में रख दें। ध्यान रहे कि सेब को दूसरी सब्जियों के साथ ना रखें।

अगर है ज्यादा सेब तो क्या करें

अगर घर में ज्यादा मात्रा में सेब हैं तो इन्हें फ्रिज में स्टोर करने की बजाय किसी अंधेरी जगह पर ऱखें। जहां का तापामान ठंडा हो। साथ ही हर एक सेब को किसी क्राफ्ट पेपर में लपेंटे। कागज सेब को खराब होन से बचाता है। इन सारे सेब को किसी टोकरी या ट्रे में रखें। अगर आप बिना कागज लपेटे सेब को एक साथ रखेंगे तो सेब जल्दी खराब हो जाएंगे।

साथ ही समय-समय पर देखते रहें कि कोई सेब खराब ना हो गया हो। अगर खऱाब दिखे तो फौरन उसे हटा दें। नहीं तो सारे सेब खराब होना शुरू हो जाएंगे।

कटे सेब को रखें ऐसे

अगर आप कटे सेब को रखना ही चाहते हैं तो इसके टुकड़ों पर नींबू का रस लगाकर रखते हैं। नींबू के रस में मौजूद साइट्रिक एसिड सेब के ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है। सबसे पहले कटे सेब को अलग रखें और किसी कटोरी में नींबू के एक चम्मच रस में पानी मिला लें। फिर इस पानी में कटे सेब को डालकर रख दें। करीब 3 से 4 मिनट बाद इसे छानकर रख लें।

जान्हवी कपूर के दिखे एक के बाद एक दो लुक, साड़ी में बेहद हसीन नजर आईं

जान्हवी कपूर बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस में शामिल होती जा रही हैं। जिनकी एक झलक को फैंस बेताब रहते हैं। बोल्ड और ग्लैमरस कपड़े हो या फिर छह गज की साड़ी, जान्हवी कपूर दोनों ही लुक में गजब ढाती हैं। एक बार फिर उनके लुक्स के चर्चे हो रहे हैं। फिल्म मिली के प्रमोशन के लिए तैयार जान्हवी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर आई हैं। जिसमे वो बेहद हसीन दिख रही हैं। वहीं उनके ये क्लासिल लुक फैंस को मां श्रीदेवी की याद दिला रहे हैं। इन तस्वीरों को जान्हवी कपूर ने साझा किया है।

हैदराबाद फिल्म 'मिली' के प्रमोशन के लिए पहुंची जान्हवी कपूर ने अपने लिए बिल्कुल देसी लुक चुना था। जो साउथ के ट्रेडिशन के हिसाब से था। नीले कलर की खूबसूरत कांजीवरम साड़ी में लिपटी जान्हवी शानदार दिख रही हैं। जिसे उन्होने स्लीवलेस नीले सैटिन के ब्लाउज को मैच किया है। बात करें जान्हवी की कांजीवरम साड़ी की तो इस साड़ी पर सिल्वर कलर के धागों से जरी का वर्क था। वहीं ये साड़ी काफी भारी भी दिख रही थी।

जिसे जान्हवी ने बालों में गजरे के साथ कॉम्पिलेंट किया है। कानों में कुंदन के भारी-भरकम झुमके और माथे पर बिंदी के साथ इस लुक को कंप्लीट किया गया है। जबकि वेल डिफाइन आईब्रो, विंग्ड आईलाइनर और आंखों में काजल के साथ न्यूड शेड की लिपस्टिक जान्हवी कपूर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। जान्हवी का ये लुक देख फैंस को उनकी मां श्रीदेवी की याद आ रही है।

जान्हवी ने एक दिन पहले फिल्म मिली के प्रमोशन के लिए हरे रंग की प्रिंटेड साड़ी को चुना था। जिसके साथ वो गोल्डन कलर के सिकुइन वर्क वाले ब्लाउज को पहने दिखीं। स्पैगेटी स्लीव और डीप प्लजिंग नेकलाइन ब्लाउज के साथ प्रिंटेड साड़ी का मैच काफी खूबसूरत दिख रहा है। जिसे देख आप भी इंस्पिरेशन ले सकती हैं। वहीं इस हरे रंग की साड़ी को जान्हवी ने गोल्डन हैवी ईयररिंग्स के साथ पेयर किया है। जबकि खुले बालों के साथ मेकअप को डार्क और ब्राइट रखा गया है। पिंक ब्लश चिक्स और शार्प कान्ट्यूरिंग के साथ ग्लॉसी न्यूड शेड पिंक कलर जान्हवी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं।

वित्तीय फैसलों पर पत्नी से खुलकर करें बात, लक्ष्यों को दें प्राथमिकता

पति और पत्नी के बीच सामंजस्य के कई कारक होते हैं। अगर आपके अपने जीवनसाथी के साथ पैसों को लेकर आपका अच्छा तालमेल नहीं है तो आप अच्छे रिश्ते में नहीं हैं। इसलिए, पैसों के इस्तेमाल के साथ अन्य वित्तीय फैसले लेते समय पत्नी को भी विश्वास में लें और उनसे खुलकर बातचीत करें।

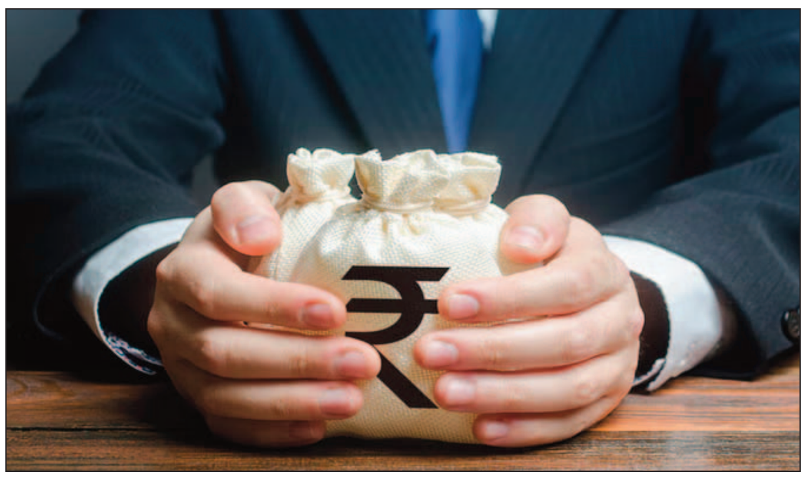

शादी एक निवेश की तरह है। यह एक लंबे समय तक चलने वाला और एक गंभीर मसला है। किसी भी निवेश की तरह, शादी में भी कुछ उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन अंततः आप एक-दूसरे से एक बंधन में बंधे होते हैं। मैंने ऐसे कई परिवारों को देखा है जो एक साथ खूब मौज-मस्ती करते हैं। खूब यात्रा करते हैं, लेकिन पैसे खर्च करने पर एक-दूसरे से बहुत कम बात करते हैं। एक दंपती होकर भी अगर पैसे के बारे में खुलकर बात नहीं करते तो आगे चलकर यह बड़े मनमुटाव का कारण बन सकता है।

हाल के दिनों में मेरे मित्र अजय के कुछ वित्तीय फैसले उनकी पत्नी आरती को अच्छे नहीं लगे। बेफिक्र होकर ज्यादा खर्च करने के उनके तरीकों ने मुझे भी परेशान किया, लेकिन मुझे पता था कि दोस्ती में अपनी सीमाएं होती हैं। मैंने आरती से सहजता से बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे अजय बड़े वित्तीय फैसलों पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे थे। उनकी 20 साल की बेटी की कुछ वर्षों में शादी हो जाएगी और बेटा दो साल बाद कॉलेज में चला जाएगा। रिटायरमेंट के बारे में भी कोई प्लानिंग नहीं है, जिसके बारे में वह चिंतित रहती थीं। अजय वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता दिए बिना अपना जीवन बड़ी बेफिक्री से जी रहा था। अजय सिर्फ दिमागी गुणा गणित में विश्वास करते थे, जिसका मतलब था कि वह अक्सर मानते थे कि उनके पास वास्तव में जितना पैसा था, उससे कहीं अधिक पैसा है।

पैसा खर्च करने पर चर्चा को रहें तैयार

सभी पति-पत्नी को मेरा सुझाव है कि उन्हें पैसे खर्च करने पर चर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका जीवनसाथी मानता है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं और वह नौकरी छोड़ने का फैसला करता है, तो क्या आप वाकई इसके लिए तैयार हैं? या यदि आप कल अपना खुद का बिजनेस करने में हाथ आजमाने का निर्णय लेते हैं तो दोनों की मिली जुली राशि आपको इसकी अनुमति देती है?

सूची बनाकर कर सकते हैं अच्छी शुरुआत

स्वस्थ वित्तीय संबंध की अच्छी शुरुआत एक वित्तीय सूची बनाकर सकते हैं। मसलन, आपके पास क्या है, आप पर क्या बकाया है, कार्यस्थल पर आपको क्या लाभ मिलता है, आपके वित्तीय लक्ष्य और भविष्य की उम्मीदें क्या हैं आदि। इस बारे में सोचें कि आप साथ मिलकर क्या हासिल करना चाहते हैं। साझा जीवन में आगे बढ़ने पर आपको कैसे एडजस्ट करना होगा।

मनी मैटर में जब जीवनसाथी सहयोगी न हो

लेकिन, क्या होगा अगर आपका जीवन साथी इन मनी मैटर में सहयोग नहीं करता है? पति-पत्नी के रूप में आपके वित्तीय लक्ष्य समान होने चाहिए और इस पर मिलजुल कर फैसले लेने की जरूरत होती है। पैसे के बारे में एक-दूसरे से खुलकर बात करें। क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। यहां तक कि ठीक से शादियां करने में भी कितना होम वर्क करना पड़ता है। खुले माहौल में बातचीत के साथ, एक रोडमैप बनाएं जो हर पार्टनर के लक्ष्यों और उनके पर्सनल हिस्ट्री पर भी विचार करे। जीवन की परिस्थितियों के कारण पैसे को लेकर हमारी प्रतिक्रिया अलग-अलग होती है। लेकिन, एक टीम के रूप में एक साथ काम करने का कमिटमेंट, सफलता का मार्ग तो प्रशस्त ही करता है, साथ थी मन की शांति भी सुनिश्चित हो जाती है।

तुम्हारा, मेरा व हमारा बजट भी अच्छी आदत

'तुम्हारा, मेरा व हमारा' बजट बनाना भी अच्छी आदत है। यदि आप दोनों नौकरीपेशा हैं, तो आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि कौन कितना खर्च करेगा। यदि आपका साथी कमा नहीं रहा है, तो यह और भी महत्वपूर्ण है कि आप उनके साथ बिना कुछ छुपाये आमदनी साझा करें ताकि उन्हें पता चल सके कि आप वित्तीय रूप से कहां खड़े हैं। इससे उन्हें वास्तविक स्थिति जानने और अपनी वित्तीय अपेक्षाओं को समायोजित करने में मदद मिलेगी। अपने जीवनसाथी को इसमें शामिल कर परिवार के सभी वित्तीय निर्णयों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार मानेंगे और ऐसा करने से खुद को भी राहत महसूस होगी।

पेट्रोल-डीजल निर्यात पर सरकार का बड़ा एक्शन, अचानक बढ़ा दिया टैक्स

नई दिल्ली, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच भारत सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। भारी मुनाफा कमाने वाली रिफाइनिंग कंपनियों पर नकेल कसते हुए केंद्र ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में बड़ा इजाफा कर दिया है। यह सख्त कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वैश्विक बाजार की स्थितियों का फायदा उठाकर तेल उत्पादक कंपनियां मोटा मुनाफा काट रही थीं।

इतनी बढ़ गई टैक्स की दरें

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स में यह बदलाव 3 अगस्त से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अब रिफाइनरी कंपनियों को पेट्रोल के निर्यात पर 2.5 रुपये की जगह 3.5 रुपये प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स चुकाना होगा। वहीं, डीजल के निर्यात पर सरकार ने और भी बड़ा फैसला लेते हुए इस टैक्स को 15.5 रुपये से सीधे बढ़ाकर 24 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों और निर्यात से हो रहे अप्रत्याशित मुनाफे को संतुलित करने के लिए ही यह दरें बढ़ाई गई हैं।

आखिर क्या होता है विंडफॉल टैक्स?

पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले इस विशेष टैक्स की सरकार हर 15 दिन में समीक्षा करती है। दरअसल, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम अचानक काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो तेल उत्पादक और रिफाइनिंग कंपनियों को सामान्य से कहीं अधिक और बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के फायदा होने लगता है। कंपनियों की इसी अप्रत्याशित अतिरिक्त कमाई के एक हिस्से को सरकार टैक्स के रूप में वसूलती है, जिसे आर्थिक भाषा में 'विंडफॉल टैक्स' कहा जाता है।

क्या आपके शहर में महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस भारी बढ़ोतरी से तेल कंपनियों के निर्यात मार्जिन पर सीधा असर पड़ना तय है, जिससे उनके मुनाफे में बड़ी सेंध लग सकती है। हालांकि, आम जनता के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि इस फैसले का घरेलू बाजार में मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर तुरंत कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। देश के भीतर ईंधन की कीमतें वैश्विक क्रूड ऑयल के भाव और कई अन्य स्थानीय कारकों पर निर्भर करती हैं, इसलिए पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को पुरानी कीमत ही चुकानी होगी। अब निवेशकों और आम लोगों की नजर आने वाले दिनों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और सरकार की अगली समीक्षा बैठक पर टिकी रहेगी।

सोने और चांदी में तेजी के साथ कारोबार, कीमतें एक प्रतिशत तक बढ़ीं

सोने और चांदी की शुरुआत मंगलवार को तेजी के साथ हुई और दोनों कीमती धातुओं में करीब एक प्रतिशत की बढ़त देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अक्टूबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,42,915 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 1,43,559 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला।

सुबह 9:50 पर यह 555 रुपए या 0.39 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,43,470 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। अब तक के कारोबार में सोने ने 1,43,365 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,43,915 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ।

सोने के साथ चांदी में भी तेजी देखी गई।

चांदी का 4 सितंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,16,746 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 2,18,143 रुपए प्रति किलो पर खुला।

फिलहाल यह 2,354 रुपए या 1.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,19,100 रुपए प्रति किलो पर खुला।

अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,18,143 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 2,19,896 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। कॉमेक्स पर सोना 0.55 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,113 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.98 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59 डॉलर प्रति औंस पर था।

इसके अलावा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 'गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स' रिपोर्ट में बताया गया कि 2026 की दूसरी तिमाही में सोने की कुल मांग सालाना आधार पर 1,269 टन पर स्थिर रही। वहीं, साल की पहली छमाही मांग सालाना आधार पर 2 प्रतिशत बढ़कर अनुमानित 2,522 टन (जिसकी कीमत 380 अरब डॉलर थी) हो गई है।

साल की दूसरी तिमाही में गोल्ड ईटीएफ, बार और सिक्कों में निवेश घटकर 262 टन रह गया। इस गिरावट की मुख्य वजह दूसरी तिमाही में गोल्ड-बैक्ड ईटीएफ से 45 टन की निकासी थी, हालांकि साल की पहली छमाही में ईटीएफ की मांग 18 टन के साथ थोड़ी सकारात्मक बनी रही। बार और सिक्कों में निवेश काफी हद तक स्थिर रहा; दूसरी तिमाही में इसमें साल-दर-साल सिर्फ 3 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि पहली छमाही की मांग पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 21 प्रतिशत ज्यादा रही, जिसकी वजह पहली तिमाही में हुई जबरदस्त मांग थी।

गाजा में हमास के हथियार डालने तक हम पीछे नहीं हटेंगे... पीएम नेतन्याहू के बयान से अधर में शांति समझौता

वॉशिंगटन, एजेंसी। गाजा क्षेत्र में शांति बहाली की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका भी शांति समझौता कराने में जुटा हुआ है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा में अपनी मौजूदा जगहों से तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं छोड़ देता। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से घोषित हालिया शांति समझौते पर भी सवाल उठाए।

नेतन्याहू की ओर से कल मंगलवार को दिए बयानों ने हमास के हथियार छोड़ने के समझौते पर और संदेह पैदा कर दिया है, जिसे क्षेत्र में जंग खत्म करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा था। साथ ही इसे नेतन्याहू का ट्रंप प्रशासन के साथ मतभेद का एक दुर्लभ सार्वजनिक उदाहरण भी माना जा रहा है।

इजराइल चुनाव में नेतन्याहू की बड़ी चुनौती

इस समझौते में हमास से हथियार रखने की प्रक्रिया शुरू करने और इजराइल से हमले रोकने और गाजा के उस करीब 60% हिस्से से पीछे हटने की बात कही गई थी जिस पर अभी उसका कब्जा बना हुआ है। यह अक्टूबर के युद्धविराम समझौते पर आधारित था, जिसने बड़े सैन्य अभियानों को खत्म किया और गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए अन्य शेष लोगों की रिहाई सुनिश्चित की, हालांकि अन्य मोर्चों पर यह प्रक्रिया रुक गई।

इजराइल में 2 महीने बाद अक्टूबर में चुनाव होने हैं और नेतन्याहू को फिर से जीत हासिल करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पीएम ने अपनी बात दोहराई कि हथियार छोड़ने की प्रक्रिया सबसे पहले होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइली सेनाएं "अपनी, अपने क्षेत्र और अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जो भी जरूरी होगा, वह करती रहेंगी।" सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पीएम नेतन्याहू ने कहा, "ट्रंप प्रशासन ने हमें एक ड्राफ्ट भेजा है। लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। यह हमारा ड्राफ्ट नहीं है। हमने अपनी टिप्पणियां भेज दी है और यही हमारा रुख है।"

दर्जनों लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार

इससे पहले कल मंगलवार को, करीब 3 साल पहले 2023 में गाजा में हुए एक घातक इजराइली हमले में मारे गए 100 से अधिक लोगों के सामूहिक अंतिम संस्कार के लिए बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग इकट्ठा हुए। हमास के साथ जंग शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद, 22 नवंबर 2023 को गाजा सिटी के सबरा इलाके में इजराइली लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ हमले कर एक रिहायशी इलाके को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए थे।

हमले के तुरंत बाद साधारण औजारों और हाथों के जरिए शवों की तलाश की गई जिसमें करीब 40 शव बरामद किए गए, लेकिन ज्यादातर शव मलबे के नीचे दबे रह गए थे। हमास युद्ध के सबसे घातक हमलों में से एक में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर, पहले युद्धविराम से ठीक पहले मची अफरा-तफरी की वजह से जनता तक पहुंचने में कई दिन लग गए।

खुदाई में मिले 40 बच्चों समेत 112 लोगों के शव

हमास द्वारा संचालित आंतरिक मंत्रालय के तहत काम करने वाली रेस्क्यू एजेंसी 'सिविल डिफेंस' के अनुसार, वीकंड में बचावकर्मियों ने नष्ट हो चुकी इमारतों की खुदाई की और 112 पीड़ितों के अवशेष बरामद किए, जिनमें 40 बच्चे भी शामिल थे। एजेंसी का कहना है कि अभी भी 157 शव नहीं मिले हैं।

अंतिम संस्कार की प्रार्थना के बाद, एक शख्स ने समाचार एजेंसी 'द एसोसिएटेड प्रेस' को बताया, "मारे गए इन लोगों का बस यही अपराध था कि वे अपने घरों में बने रहे और हिम्मत बनाए रखी, यह सोचकर कि उनके घर उनकी रक्षा करेंगे।" "जो लोग अभी भी लापता हैं, उनके बारे में ऐसा लगता है "मानो उनके शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गए हों।" जंग शुरू होने के शुरुआती महीनों में मारे गए लोगों के शव अब धीरे-धीरे मिल रहे हैं, क्योंकि कमजोर युद्धविराम की वजह से तबाह हो चुके गाजा के कुछ हिस्सों में ऐसी कोशिशें आगे बढ़ पा रही हैं। इन शवों के मिलने से युद्ध में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है।

अब तक 73 हजार से अधिक लोग मारे गए

7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास की ओर से किए गए हमले में करीब 1,200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल की ओर से किए जवाबी कार्रवाई की गई और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इज़राइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 73,377 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें युद्धविराम के बाद की मौतें भी शामिल हैं। मंत्रालय के रिकॉर्ड विभाग के प्रमुख जाहिर अल-वहीदी ने समाचार एजेंसी AP को बताया कि वहां रह रहे रिश्तेदारों के अनुसार, कम से कम 7,400 से अधिक लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अल-वहीदी ने कहा कि जबकि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि कुछ मामलों में एक ही बमबारी में पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया, ऐसे में लापता लोगों की जानकारी देने वाला कोई बचा ही नहीं। अब मंगलवार को जिन लोगों के लिए शोक मनाया गया, वे हसायना और अबू शरिया कबीले के रिहायशी इलाके के रहने वाले लोग थे। इनमें से कई तो आपस में रिश्तेदार भी थे।

भारत के FCRA कानून में बदलाव पर अमेरिकी सांसद की आपत्ति, बोले- अमेरिका से रिश्तों पर पड़ सकता है असर

वॉशिंगटन, एजेंसी। भारत में विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाले विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में प्रस्तावित बदलाव को लेकर अमेरिका के एक सांसद ने चिंता जताई है। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया से रिपब्लिकन सांसद राइली मूर ने कहा है कि अगर यह संशोधन मौजूदा रूप में लागू हुआ तो भारत सरकार को चर्चों और धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल सकता है। उन्होंने इसे ईसाई समुदाय के खिलाफ कदम बताते हुए कहा कि इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है।

राइली मूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारत में ईसाई धर्म का इतिहास करीब दो हजार साल पुराना है। उनके मुताबिक, सेंट थॉमस ईसा मसीह के पुनरुत्थान के कुछ दशक बाद भारत के मालाबार तट पहुंचे थे। मूर ने कहा कि अब भारतीय संसद FCRA कानून में ऐसे बदलाव पर विचार कर रही है, जिससे सरकार चर्चों और धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सके। उन्होंने इसे ईसाइयों के खिलाफ सीधा हमला बताया और कहा कि अगर यह बिल इसी रूप में आगे बढ़ता है तो यह भारत-अमेरिका संबंधों के लिए चिंता का विषय होगा।

नए नियम में क्या हैं प्रावधान?

दरअसल, विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 में सरकार को एक 'डेजिग्नेटेड अथॉरिटी' (नामित प्राधिकरण) बनाने का प्रस्ताव है। अगर किसी संस्था का FCRA पंजीकरण रद्द हो जाता है, संस्था खुद उसे वापस कर देती है या समय पर नवीनीकरण नहीं होने के कारण उसकी मान्यता समाप्त हो जाती है, तो यह प्राधिकरण उस संस्था को मिले विदेशी चंदे और उससे बनाई गई संपत्तियों का प्रबंधन संभाल सकेगा।

हालांकि, प्रस्तावित विधेयक में यह भी साफ कहा गया है कि अगर ऐसी संपत्ति किसी पूजा स्थल से जुड़ी होगी, तो उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा और उसे उसी रूप में बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा, FCRA के उल्लंघन पर अधिकतम सजा 5 साल से घटाकर 1 साल करने का भी प्रस्ताव है। मोदी सरकार अगले सप्ताह इस विधेयक को लोकसभा में पेश कर सकती है।

कितने संगठनों के कितनी फंडिंग मिली?

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2019 से 2022 के बीच 13,520 संगठनों को कुल 55,741 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग मिली। वहीं, 15 जुलाई 2026 तक FCRA पोर्टल पर 14,449 संस्थाओं का पंजीकरण सक्रिय था। इसके अलावा 22,498 पंजीकरण रद्द हो चुके हैं, जबकि 15,212 पंजीकरण समय पर नवीनीकरण नहीं होने के कारण स्वतः समाप्त माने गए हैं।

PoK में दो महीने में 90 लोगों की मौत, पाकिस्तान की क्रूरता से गुस्से में भारत; चुनाव को भी करार दिया मजाक

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (PoK) में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर लोगों के साथ क्रूरता की जा रही है। भारत भी वहां के हालात को लेकर चिंतित है। भारत ने कल मंगलवार को PoK में आम लोगों पर लगातार बर्बर कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। भारत ने कहा कि जून से अब तक कम से कम 90 आम लोगों की जान जा चुकी है और इलाके में हुए लोकल चुनावों को "पूरी तरह से मजाक" करार दिया और दिखावा बताया।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर 2 हफ्ते में होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे वहां आम लोगों पर हो रहे अत्याचारों के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराएं।

उन्होंने कहा, "इस साल जून से अब तक, लगातार कार्रवाई में कम से कम 90 आम लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तानी सरकार स्थानीय लोगों की आवाज दबाने की कोशिश में लगी है। उसने लोगों की नाराजगी का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, डराने-धमकाने और दबाने से दिया है, और अब एक खोखले चुनावी काम के जरिए अपनी बात मनवाना चाहती है।"

प्रवक्ता जायसवाल ने PoK में हाल ही में हुए लोकल चुनावों की भी आलोचना की और कहा कि चुनावी प्रक्रिया वहां की जमीनी हकीकत को छिपा नहीं सकती। उन्होंने कहा, "PoK में यह तथाकथित लोकल चुनाव पूरी तरह से मजाक है। सच्चाई तो पाकिस्तानी सेना की ओर से लोगों के विरोध और बेरहमी से की जा रही हत्याएं हैं।

झारखंड में छात्रों के आंदोलन के साथ CJP फाउंडर अभिजीत दिपके, समर्थन देने जाएंगे रांची

नई दिल्ली। छत्रपति संभाजीनगर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की दो दिवसीय कोर कमेटी की बैठक शुरू है। बैठक के पहले दिन संगठन के प्रमुख अभिजीत दिपके और प्रवक्ता सौरभ दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए संगठन की आगे की रणनीति, झारखंड छात्र आंदोलन और देशभर में संगठन के विस्तार को लेकर अपनी बात रखी।

अभिजीत दिपके ने कहा कि CJP झारखंड के छात्र आंदोलन का पूरा समर्थन करती है और संगठन का प्रतिनिधिमंडल झारखंड जाकर आंदोलनकारियों के साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि बैठक में देशभर में संगठन को मजबूत करने और आगे के रोडमैप पर चर्चा की जा रही है।

राजनीति में प्रवेश के सवाल पर दिपके ने कहा कि CJP की राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक दलों की स्थिति चिंताजनक है, जहां विधायक और सांसद लगातार दल बदल रहे हैं। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के जरिए राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सभी को साथ आना होगा। उन्होंने बताया कि बैठक में मीडिया, न्यायपालिका, बेरोजगारी और E20 नीति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी।

सोनम वांगचुक बैठक में शामिल नहीं

दिपके ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वह बैठक में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि बैठक के दूसरे दिन दोपहर दो बजे मीडिया को संगठन के अंतिम निर्णय और आगे की रणनीति की जानकारी दी जाएगी।

लाठीचार्ज और FIR वापस लेने का मुद्दा

CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन में घायल हुए छात्रों को पहले दिन से कानूनी और चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि जिन-जिन राज्यों में आंदोलन हुए, वहां के आंदोलनकारियों की भी CJP मदद कर रही है। सौरभ दास ने दावा किया कि सरकार के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत जारी है, जिसके चलते कई राज्यों में आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जा चुकी हैं, जबकि बाकी मामलों में भी कार्रवाई के लिए प्रयास जारी हैं।

'डॉक्सिंग अभियान' पर कार्रवाई की मांग

आंदोलन में शामिल छात्राओं से माफी मंगवाए जाने और उनके खिलाफ कथित ऑनलाइन अभियान पर सौरभ दास ने कहा कि छात्राओं के खिलाफ डॉक्सिंग अभियान चलाया गया, जो पूरी तरह गलत और अवैध है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अभियान में भाजपा और आरएसएस समर्थक लोग शामिल थे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सौरभ दास ने कहा कि सोनम वांगचुक CJP के मार्गदर्शक (मेंटर) हैं और संगठन आगे भी उनसे सलाह लेता रहेगा।

सिविल सर्जन ने डायरिया के प्रति जागरूकता के लिए प्रचार वाहनों को किया रवाना

» **30 अगस्त तक चलेंगे प्रचार वाहन, आयोजित होंगी विभिन्न गतिविधियाँ**

दरभंगा। डायरिया के प्रति समुदाय में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सिविल सर्जन दरभंगा डॉ. अरुण कुमार ने बुधवार को जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय से पोस्टर-बैनर और आकर्षक जिंगल्स से सुसज्जित प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन जिला के हाई रिस्क प्रखंडों सहित शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर डायरिया की शीघ्र पहचान, बचाव और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के तहत प्रचार वाहन को अगले 30 अगस्त तक संचालित किया जाएगा।

इस मौके पर सिविल सर्जन ने कहा कि शून्य से पांच साल तक के बच्चों को दिन भर में तीन या तीन से अधिक बार पतली दस्त हो तो समझना चाहिए कि बच्चा डायरिया से ग्रसित है और ऐसे में उसको तत्काल ओआरएस का घोल देना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न होने पाए। उन्होंने बताया कि डायरिया से डर नहीं कार्यक्रम के तहत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों में डायरिया से जुड़े प्रमुख संदेशों पर प्राथमिकता से चर्चा की जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि दस्त के दौरान बच्चों को तरल पदार्थ दिया जाए, दस्त होने पर बच्चों को उम्र के अनुसार 14 दिनों तक जिंक की गोली अवश्य दी जाए, स्वच्छ पेयजल का उपयोग किया जाए और खाना बनाने से पूर्व, परोसने से पूर्व और खाना खिलाने से पूर्व और बच्चों का मल साफ़ करने के बाद हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह से अवश्य धुलें।

जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिला में स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में पीएसआई इंडिया और केनव्यू के सहयोग से 'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो दस्त रोको अभियान में भी सहयोग करेंगे। कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य केंद्रों पर ओआरएस व जिंक कॉर्नर बनाए गए हैं, दीवार लेखन के जरिए भी लोगों को डायरिया के प्रति जागरूक किया जा रहा है। फ्रंट लाइन वर्कर का डायरिया के बारे में अभिमुखीकरण भी किया गया है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों के लिए ओआरएस एवं जिंक का वितरण किया जाएगा। वितरण की दैनिक प्रगति एवं लाभार्थियों का विवरण स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर नियमित रूप से दर्ज किया जाएगा, जिससे अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं समयबद्ध समीक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इस मौके पर जिला संचारी रोग पदाधिकारी डॉ. सतेंद्र कुमार मिश्रा, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक प्रभात कुमार राजू, जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी श्रीकांत शरण, जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार वंदना राज, जिला प्रतिरक्षण कार्यालय से भास्कर निषाद , पीएसआई इंडिया से संजय तरुण, अखिलेश कुमार, जिला समन्वयक जेएसआई संजय चौहान, सहित जिला स्वास्थ्य समिति और जिला प्रतिरक्षण कार्यालय के कर्मी एवं प्रखंडों से आए अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे।

अमीषा के बाद अब करीना और शिल्पा की बारी, 40 प्लस अभिनेत्रियों ने संभाली सिनेमा की जिम्मेदारी

शिल्पा शेट्टी की फिल्म 'सुखी' और करीना कपूर खान की फिल्म 'जाने जां' इस हफ्ते रिलीज हो रही हैं और दोनों इस फिल्म के प्रचार के लिए मेहनत भी खूब कर रही हैं। शिल्पा शेट्टी का तो यहां तक मानना है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह बिल्कुल एक न्यूकमर की तरह अनुभव कर रही थीं।

ओटीटी प्लेटफार्म के आने से 40 की उम्र पार कर चुकी अभिनेत्रियों को वेब सीरीज में तो अच्छे मौके मिले ही हैं, साथ ही इस उम्र को 40 पार कर चुकी कई अभिनेत्रियां फिल्मों के लीड रोल में भी अपने स्टारडम को बरकरार रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। शिल्पा शेट्टी की फिल्म 'सुखी' और करीना कपूर खान की फिल्म 'जाने जां' इस हफ्ते रिलीज हो रही हैं और दोनों इस फिल्म के प्रचार के लिए मेहनत भी खूब कर रही हैं। शिल्पा शेट्टी का तो यहां तक मानना है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह बिल्कुल एक न्यूकमर की तरह अनुभव कर रही थीं। आइए जानते हैं शिल्पा शेट्टी के अलावा हिंदी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों के बारे में जो 40 की उम्र पार करने के बाद भी लीड रोल की फिल्में कर रही हैं...

शिल्पा शेट्टी

शाहरुख खान की फिल्म 'बाजीगर' से बड़े परदे पर डेब्यू करने वाली अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'सुखी' को लेकर काफी उत्साहित हैं। यह फिल्म भी इसी हफ्ते 22 सितंबर को रिलीज हो रही है। नवोदित निर्देशक सोनल जोशी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी एक ऐसी गृहिणी सुखप्रीत 'सुखी' कालरा की भूमिका निभा रही हैं जो शादी के बाद अपने पति और बच्चे की देखभाल में अपनी खुशियों को भुला देती है। 48 साल की हो चुकी शिल्पा शेट्टी की पिछली रिलीज फिल्म 'निकम्मा' बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही थी।

अमीषा पटेल

अभिनेत्री अमीषा पटेल के करियर के लिए फिल्म 'गदर -2' किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हुई है। पिछले कई वर्षों से गर्दिश में चल रहे अमीषा पटेल के सितारे इस फिल्म से बुलंद हो गए। इस फिल्म ने न सिर्फ अमीषा पटेल बल्कि सनी देओल के लुढ़कते करियर को भी संभाल दिया और इस साल सनी देओल इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे के रूप में उभरे हैं। अमीषा पटेल को कतई उम्मीद नहीं थी कि 47 साल की उम्र में उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 'गदर 2' का अब तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 519.43 करोड़ रूपये हो चुका है।

रानी मुखर्जी

अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म 'मिसेस चटर्जी वर्सेस नार्वे' की कहानी उन तमाम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जिनको संघर्ष में किसी का साथ नहीं मिलता। यहां तक अपने परिवार और पति तक का भी नहीं। इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने देबीना चटर्जी नाम की एक महिला की भूमिका निभाई थी जो अपने बच्चो की कस्टडी पाने के लिए जी जान से जुटी रहती है। आशिमा छिब्बर के निर्देशन में बनी ये फिल्म कारोबारी मामले में भी सफल फिल्म रही।

दीया मिर्जा

काफी लंबे समय के बाद अभिनेत्री दिया मिर्जा निर्देशक अनुभव सिन्हा की फिल्म 'भीड़' में नजर आईं। इस फिल्म में दीया ने गीतांजलि की भूमिका निभाई थी जो लॉकडाउन में फंसी अपनी बेटी को लेने जाती हैं और रास्ते में खुद ही फंस जाती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 42 साल की हो चुकी दीया मिर्जा जल्द ही शाहरुख खान की फिल्म 'डंकी' के एक खास किरदार में नजर आएंगी। तापसी पन्नू की प्रोडक्शन कंपनी की फिल्म 'धक धक' में भी उनका एक खास रोल है।

तब्बू

52 साल की उम्र में भी अभिनेत्री तब्बू फिल्मों में खूब सक्रीय हैं। उनकी 'भूल भुलैया 2' और 'दृश्यम 2' जैसी फिल्में हिट रही हैं। 'कुत्ते' और 'भोला' में भी उनके किरदार की खूब तारीफें हुईं। अब अगले महीने वह नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म 'खुफिया' में नजर आने वाली हैं। तब्बू के पास इन दिनों नई फिल्मों के प्रस्तावों की लाइन लगी हुई है।

ऐश्वर्या राय बच्चन

निर्माता-निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म 'पोंनियिन सेल्वन' के दोनों भाग में ऐश्वर्या राय बच्चन का अभिनय कौशल कमाल का दिखा है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन की सौंदर्य को उनकी पूरी गरिमा और आभा के साथ इस फिल्म में पेश किया गया है। 50 की हो चुकी ऐश्वर्या राय बच्चन न सिर्फ फिल्म में खूब खूबसूरत लगी हैं, बल्कि अपने अभिनय कौशल से भी उन्होंने दर्शकों को काफी प्रभावित किया। दोनों फिल्मों के तमिल संस्करणों का कलेक्शन कमाल का रहा, हालांकि इनके हिंदी संस्करण उतने प्रभावी नहीं रहे।

काजोल

अभिनेत्री काजोल की फिल्म रेवती के निर्देशन में बनी फिल्म 'सलाम वेंकी' में लाइलाज बीमारियों से जूझते इंसानो के दुःख के साथ साथ उसके चारो तरफ बसी दुनिया पर इसके चलते असर को भांपने की कोशिश की गई थी। 49 साल की उम्र में काजोल का अभिनय उम्र के बढ़ने के साथ साथ परिपक्व होता दिख रहा है। मां के किरदार में इस फिल्म में काजोल की बेहतरीन अदाकारी देखने को मिली। फिल्मों के अलावा काजोल इन दिनों वेब सीरीज में भी सक्रिय हैं।

पूजा भट्ट

निर्देशक आर बाल्की की फिल्म 'चुप' से अभिनेत्री पूजा ने 49 की उम्र में बड़े परदे पर वापसी की। इस फिल्म में पूजा भट्ट ने आपराधिक मनोवैज्ञानिक डॉ जेनोबिया श्रॉफ की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को लेकर पूजा भट्ट काफी उत्साहित थी, लेकिन ये फिल्म दर्शकों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स की थी जो फिल्म समीक्षकों को चुप कराने निकलता है।

रवीना टंडन

अभिनेत्री रवीना टंडन ने फिल्म 'केजीएफः चैप्टर 2' में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्रेरित एक किरदार रामिका सेन की भूमिका निभाई थी। हालांकि इस फिल्म में साउथ सिनेमा के सुपर स्टार यश और संजय दत्त की मुख्य भूमिका थी लेकिन छोटे से किरदार में भी रवीना टंडन की दमदार अदाकारी देखने को मिली थी। 49 की उम्र में फिल्मों के अलावा रवीना टंडन की जबरदस्त अदाकारी वेब सीरीज में भी खूब देखने को मिली है। हाल ही में घोषित हुई फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में भी वह एक खास किरदार में नजर आएंगी।

करीना कपूर खान

अपनी पिछली हिंदी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में करीना कपूर खान ने आमिर खान के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में करीना कपूर खान ने रूपा डिसूजा चड्ढा की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हॉलीवुड की फिल्म 'फॉरेस्ट गम्प' का हिंदी रूपांतरण था। फिल्म समीक्षकों ने इस फिल्म को खूब सराहा, लेकिन बॉयकॉट ट्रेंड के चलते यह फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में सफल नहीं रही। 43 साल की हो चुकी करीना कपूर की अगली फिल्म 'जाने जां' 21 सितंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है, यह करीना का ओटीटी डेब्यू भी है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित । शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com